

मुंबई में बारिश का कहर: मानखुर्द में अवैध चॉल गिरी, 6 की दर्दनाक मौत, एफआईआर दर्ज

मुंबई, 06 जुलाई। मुंबई के मानखुर्द इलाके में एक गैर-कानूनी चार मंजिला इमारत के गिरने से छह लोगों की मौत हो गई। इस घटना के बाद एक अपराधिक मामला दर्ज किया गया है और दो लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इस घटना ने बिना मंजूरी के हो रहे निर्माण और सिविक निगरानी को लेकर नई चिंता पैदा कर दी है। यह घटना रविवार रात करीब 8.30 बजे जनता नगर में हनुमान मंदिर के पीछे हुई। भारी बारिश के बीच 'चाल नंबर 5' (जो जमीनी मंजिल के अलावा तीन मंजिल ऊँची इमारत थी) का एक हिस्सा अचानक ढह गया। शुरूआती रिपोर्टों के मुताबिक, दो से तीन रिहायशी घर ढह गए, जिससे कई निवासी मलबे के नीचे दब गए। इमारत गिरने के तुरंत बाद

इमरजेंसी टीमें मौके पर पहुंचीं। मुंबई फायर ब्रिगेड (MFB), मुंबई पुलिस, बृहन्मुंबई नगर निगम (BMC) और 108 एम्बुलेंस सेवा के कर्मचारियों ने पूरी रात बड़े पैमाने पर बचाव अभियान चलाया। मलबे से कई लोगों को बाहर निकाला गया, लेकिन छह लोगों की मौत हो गई। इस हादसे के बाद अधिकारियों ने इमारत के निर्माण को लेकर अपराधिक जांच शुरू कर दी है। मानखुर्द पुलिस स्टेशन में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 105 और 3(5) के तहत FIR दर्ज की गई है।

पुलिस के मुताबिक, गिरी हुई इमारत अवैध रूप से बनाई गई चार मंजिला इमारत थी। इमारत के मालिक, ठेकेदार, झोपड़ी के मालिक और अवैध निर्माण के लिए जिम्मेदार



अन्य लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। जांचकर्ता इस बात की जांच करेंगे कि क्या इमारत ने निर्माण नियमों का उल्लंघन किया था और क्या लापरवाही के कारण यह हादसा हुआ। एक अहम घटनाक्रम में, अधिकारियों ने बताया कि आरोपियों की सूची में ऐसे निजी व्यक्ति और सरकारी अधिकारी भी शामिल हैं, जिन्होंने कथित तौर पर अवैध निर्माण में मदद की या उसे संभव बनाया। उनकी भूमिकाओं की जांच की जा रही है और अधिकारी नियमों को लागू करने और रेगुलेटरी निगरानी में हुई संभावित चूक की भी जांच कर रहे हैं।

अमेरिकी दावे पर नेतन्याहू का करारा जवाब, कहा- 'भारत जैसा दोस्त हमारे साथ'

इजरायल, 6 जुलाई। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के उस बयान से असहमत जताई है, जिसमें वेंस ने कहा था कि अमेरिका ही इजरायल का एकमात्र प्रभावशाली सहयोगी है। एक साक्षात्कार में नेतन्याहू ने कहा कि इजरायल को अमेरिका के अलावा भारत सहित कई अन्य देशों का भी समर्थन प्राप्त है और उसके वैश्विक सहयोगियों का दायरा कहीं अधिक व्यापक है। नेतन्याहू ने बातचीत के दौरान भारत का जिक्र करते हुए कहा कि उन्हें भारत से व्यापक समर्थन मिलता है। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर भी बड़ी संख्या में भारतीय उनका समर्थन करते हैं। उन्होंने कहा कि इजरायल के कई मित्र देश हैं, जो सुरक्षा, रक्षा, कृषि, बुद्धिमत्ता और साइबर सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में उसके साथ सहयोग बढ़ाना चाहते हैं। पिछले महीने



व्हाइट हाउस में मीडिया से बातचीत के दौरान J.D. Vance ने कहा था कि यदि वह इजरायल की कैबिनेट में होते, तो वह अपने एकमात्र शक्तिशाली सहयोगी अमेरिका की सार्वजनिक आलोचना नहीं करते। यह टिप्पणी अमेरिका-ईरान वार्ता और लेबनान में इजरायली सैन्य अभियानों को लेकर सामने आई रिपोर्टों के संदर्भ में की गई थी। नेतन्याहू ने कहा कि दुनिया के कई नेता उनसे संपर्क करते हैं और रक्षा, सैन्य रणनीति, साइबर सुरक्षा तथा अकजैसे क्षेत्रों में सहयोग की इच्छा जताते हैं। उन्होंने कहा कि इजरायल साइबर सुरक्षा क्षेत्र में दुनिया के अग्रणी देशों में शामिल है और उसकी तकनीकी विशेषज्ञता के कारण कई देश उसके साथ साझेदारी करना चाहते हैं। हाल के वर्षों में भारत और इजरायल के बीच रक्षा, कृषि, जल प्रबंधन, साइबर सुरक्षा और प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में सहयोग लगातार बढ़ा है।

MEIL ने कैगा अणुऊर्जा प्रकल्प में रचा इतिहास

मुंबई, 6 जुलाई। मेघा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर्स लिमिटेड (MEIL) ने कर्नाटक के कैगा अणुऊर्जा परियोजना के यूनिट 5 और 6 में प्रेशराइज्ड हेवी वॉटर रिएक्टर (PHWR) निर्माण के दौरान एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। कंपनी ने NPCIL के इतिहास में सबसे बड़ा विनाखंड (अखंड) कंक्रिट डालने का काम सफलतापूर्वक पूरा किया।

इस कार्य में लगभग 7,250 घनमीटर कंक्रिट का उपयोग किया गया। इतने बड़े पैमाने पर अखंड कंक्रिट डालना MEIL के लिए एक उल्लेखनीय उपलब्धि है। इससे कंपनी की इंजीनियरिंग क्षमता, सटीक योजना और उत्कृष्ट कार्यान्वयन कौशल स्पष्ट होता है।

कठिन मौसम, भारी बारिश और दुर्गम स्थान जैसी चुनौतियों के बावजूद MEIL ने अत्याधुनिक तकनीक, तापमान नियंत्रित कंक्रिट उत्पादन, बर्फ निर्माण व भंडारण क्षमता और बड़े पैमाने पर जनशक्ति की उपलब्धता सुनिश्चित कर यह काम बिना किसी रुकावट के पूरा किया। इस कार्य में सैकड़ों इंजीनियरों, तकनीशियनों, सुरक्षा कर्मियों और श्रमिकों ने दिन-रात मेहनत की। सुरक्षा के सभी नियमों का पालन करते हुए और गुणवत्ता की सभी जांचें पूरी कर यह काम सफलतापूर्वक संपन्न हुआ।

शाहजहांपुर की जलालाबाद तहसील अब कहलाएगी परशुरामपुरी, योगी कैबिनेट का बड़ा फैसला

लखनऊ, 06 जुलाई। यूपी में एक और शहर का नाम बदला! लखनऊ में मुख्यमंत्री आवास पर हुई कैबिनेट बैठक में शाहजहांपुर की जलालाबाद तहसील का नाम बदलने के प्रस्ताव को पास कर दिया गया है। योगी कैबिनेट की मंजूरी के बाद अब जलालाबाद तहसील का नया नाम 'भगवान परशुराम पुरी' होगा। सोमवार को हुई इस उच्चस्तरीय बैठक में दोनों डिप्टी सीएम और राज्य के प्रमुख मंत्रियों ने हिस्सा लिया, जहाँ इस फैसले समेत कई अन्य महत्वपूर्ण योजनाओं और प्रस्तावों को भी मंजूरी दी गई। प्रशासन जल्द ही नाम बदलने की आगे की कागजी कार्रवाई शुरू करेगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती पर सोमवार को उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की और उन्हें महान स्वतंत्रता सेनानी, शिक्षाविद तथा भारत की एकता और अखंडता के प्रबल समर्थक के रूप में याद किया। आदित्यनाथ ने यहां आयोजित एक कार्यक्रम में कहा कि देश की एकता की रक्षा करने और जम्मू-कश्मीर को मिले विशेष दर्जे का विरोध करने में डॉ. मुखर्जी

के योगदान को हमेशा याद रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि भारत माता के महान सपूत, महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और एक देश में दो विधान, दो प्रधान, दो निशान नहीं चलेगे का उद्धोष करने वाले डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की आज 125वीं पावन जयंती है। इस अवसर पर उनकी स्मृतियों को नमन करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार और प्रदेश की जनता की ओर से मैं उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सरकार से अलग होने के बाद भारतीय जनसंघ के संस्थापक अध्यक्ष के रूप में डॉ. मुखर्जी ने देश की अखंडता के लिए ह्रापक देश में दो विधान, दो प्रधान और दो निशान नहीं चलेगा का नारा दिया और जम्मू-कश्मीर की विशेष दर्जे की व्यवस्था का विरोध किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि डॉ. मुखर्जी ने जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 और तत्कालीन नेहरू सरकार की तृष्ठीकरणहकी नीति के खिलाफ जो अभियान शुरू किया था, उसे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी सरकार ने 2019 में अनुच्छेद 370 को समाप्त कर साकार किया।

भीषण हमलों से फिर दहला यूक्रेन: रूस ने बरसाई 68 मिसाइलें और 351 ड्रोन, 12 लोगों की मौत

नई दिल्ली, 06 जुलाई। रूस ने रविवार देर रात यूक्रेन की राजधानी कीव समेत कई इलाकों पर बड़े पैमाने पर मिसाइल और ड्रोन हमले किए। यूक्रेनी अधिकारियों के अनुसार, इस हमले में कम से कम 11 लोगों की मौत हो गई, जबकि 60 से अधिक लोग घायल हुए हैं। बचाव दल क्षतिग्रस्त बहुमंजिला इमारतों के मलबे में फंसे लोगों की तलाश में जुटे हैं। यूक्रेन के सैन्य प्रशासन के अनुसार, हमला सोमवार तड़के तक जारी रहा। रूस ने बैलिस्टिक मिसाइलों, कूज मिसाइलों और बड़ी संख्या में ड्रोन का इस्तेमाल किया। राजधानी में लगातार विस्फोटों की आवाजें सुनाई देती रहीं और बड़ी संख्या में लोगों ने जान बचाने के लिए मेट्रो स्टेशनों में



शरण ली। कीव के पोलिस्की जिले में एक आवासीय इमारत का हिस्सा ढह गया, जबकि दार्निस्सिया जिले में कई बहुमंजिला इमारतें क्षतिग्रस्त हो गईं। यूक्रेन की वायुसेना ने कहा कि रूस ने रातभर सैकड़ों ड्रोन और दर्जनों मिसाइलें दागीं। अधिकारियों के अनुसार, कई बैलिस्टिक

मिसाइलें अपने लक्ष्य तक पहुंचने में सफल रहीं। वायुसेना के प्रवक्ता urii lhnat ने कहा कि बैलिस्टिक मिसाइलों को रोकने के लिए अत्याधुनिक इंटरसेप्टर मिसाइलों की आवश्यकता होती है और वर्तमान में यूक्रेन को उनकी गंभीर कमी का सामना करना पड़ रहा है। यूक्रेनी अधिकारियों के अनुसार,

रूस ने इस हमले में 68 मिसाइलें और 351 ड्रोन इस्तेमाल किए। इनमें इस्कंदर-एम, एस-400 आधारित बैलिस्टिक मिसाइलें तथा जिरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइलें भी शामिल होने का दावा किया गया है। हालांकि, इन हथियारों की संख्या और सभी मिसाइलों के प्रकार की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हो सकी है। रूस के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि हमले का लक्ष्य कीव स्थित हथियार निर्माण इकाइयां, ड्रोन उत्पादन केंद्र, ईंधन भंडार, एयर डिफेंस मरम्मत केंद्र और ऊर्जा अवसरचना थे। हालांकि, इस दावे की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है। दूसरी ओर यूक्रेनी अधिकारियों का कहना है कि हमलों में कई रिहायशी इमारतें भी क्षतिग्रस्त हुईं और नागरिक हताहत हुए।

मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी पर निशाना साधा

नई दिल्ली, 06 जुलाई। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सोमवार को भारत की गिरती पासपोर्ट रैंकिंग और सालाना पर्यटकों की संख्या में कमी को लेकर केंद्र सरकार की आलोचना की। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों को भारत की वैश्विक प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने के लिए जिम्मेदार ठहराया। कांग्रेस प्रमुख ने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम और ग्लोबल सिटिजन सॉल्यूशंस का हवाला दिया, जिनके अनुसार भारत ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स में क्रमशः 80वें और 125वें स्थान पर खिसक गया है। न्होंने पासपोर्ट फीस में हालिया बढ़ोतरी को लेकर भी सरकार पर निशाना साधा और कहा कि सेवाओं में सुधार करने के बजाय, केंद्र ने पासपोर्ट को और महंगा कर दिया है। खड़गे ने एक्स पर पोस्ट किया, मोदी सरकार की

नीतियां भारत की वैश्विक प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने के लिए जिम्मेदार हैं। पीएम मोदी ने 2018 में दावा किया था: 'विदेशों में यात्रा करने और रहने वाले लोग आज भारतीय पासपोर्ट के सम्मान और ताकत को जानते हैं।' वह 'ताकत' कहाँ दिखती है? तथ्य उनके दावों को गलत साबित करते हैं। एक ग्लोबल पासपोर्ट रैंकिंग में, भारत 2013 में 74वें स्थान से गिरकर जून 2026 में 80वें स्थान पर आ गया है। एक और ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स भारत को 2026 में 125वें खराब स्थान पर रखता है। उन्होंने आगे कहा, सेवाओं को बेहतर बनाने के बजाय, मोदी सरकार ने पासपोर्ट को और महंगा कर दिया है। पासपोर्ट फीस 1,500 से बढ़ाकर 2,500 कर दी गई है, जबकि तत्काल चार्ज 5,000 तक बढ़ गए हैं।

मणिपुर : उग्रवादियों के हमले में असम राइफल्स के 2 जवानों की मौत, कई घायल

मणिपुर, 06 जुलाई। मणिपुर के उखरूल जिले में सोमवार को संदिग्ध उग्रवादियों द्वारा घात लगाकर किए गए हमले में असम राइफल्स के दो जवानों की मौत हो गई, जबकि कई अन्य घायल हो गए। पुलिस ने यह जानकारी दी। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि यह घटना अपराह करीब 1.30 बजे पहाड़ी जिले के नुंगशांग खोंग इलाके में हुई,

जब संदिग्ध उग्रवादियों ने अर्द्धसैनिक बल के काफिले पर घात लगाकर गोलीबारी कर दी। उन्होंने बताया, 'मारे गए जवानों में एक वारंट ऑफिसर और एक ड्राइवर हैं। उनकी मौत मौके पर ही हो गई। यह घटना उखरूल पुलिस थाना क्षेत्र में, जिला मुख्यालय से लगभग 17 किलोमीटर दूर नुंगशांग खोंग इलाके में हुई, जब काफिला सांशाक में



40वीं असम राइफल्स बटालियन मुख्यालय लौट रहा था।' अधिकारी ने बताया कि हमले के

बाद इलाके में अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं और पास के ही एक इलाके में केंद्रीय बलों और

मणिपुर के मुख्यमंत्री वाई. खेमचंद सिंह ने एक बयान जारी कर असम राइफल्स के दो जवानों की हत्या की कड़ी निंदा की और शोक संतप्त परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदन व्यक्त की। उन्होंने कहा कि सरकार इस तरह की बर्बर हिंसा को बर्दाश्त नहीं करेगी और इन अत्याचारों को मूकदर्शक बनकर नहीं देखेगी।



DAKS REHAB CENTRE

(PARALYSIS PHYSIOTHERPHY CENTER AND OLD AGE HOME)

Contact us: 9820519851

विलिंडिंग नंबर 3, फ्लॉट नंबर 3, आदर्श घरकुल सोसायटी सायन कोलीवाडा जीटीवी नगर मुंबई-37

- * Stroke/Paralysis/Complete Rehab Centre
- * बाहर से आये रोगी और उनके परिजनो के ठहरने कि व्यवस्था
- * वृद्ध लोगों के लिए रहने की सुविधा उपलब्ध
- * DM/HT/THYROID इन सब से कैसे बचें
- * NGO में मिलनेवाली सहायता को लोगों में देना
- * चिकिस्ता उपकरणो को किराये और बिक्री सुविधा उपलब्ध
- * एम्बुलेंस सेवा उपलब्ध
- * पोस्ट ऑपरेटिव रिहैब सेंटर
- * मरीजों के लिए घर पर 12 और 24 घंटे जीडीए परिचारक
- * विशेषज्ञ डॉक्टरों से ऑनलाइन और ऑफलाइन परामर्श की सुविधा उपलब्ध
- * मासिक ईएमआई के आधार पर व्यक्तियों, परिवारो और माता-पिता के लिए स्वास्थ्य निती की चिकिस्ता सुविधा उपलब्ध







NEW LIGHT CLASSES

TRADITION OF EXCELLENCE

2nd Floor, Sheetal Bldg. Near Dianond Talkies, L. T. Road, Borivali (West) Mumbai - 400 092 Maharashtra

ADMISSIONS OPEN

ALL OVER INDIA

ENROLL NOW



SMART CLASSROOM

(ONLINE/OFFLINE)

Courses Offered

- Std. XI & XII (Sci.)
- MHT-CET
- NEET
- Polytechnic & Engg
- JEE
- Physics and Maths (Main & Advance)
- (ICSE, CBSE, ISC)

M: 9833240148 | E: edu@newlightclasses.com | W: www.newlightclasses.com

TIWARI'S SARASWATI CLASSES

— Since 1992 —
Parents' First Choice for 34+ Years

Prof. Dr. Dayanand Tiwari
Founder & Academic Director

ADMISSIONS OPEN

9th | 10th | 11th | 12th SCIENCE

NEET | JEE | MHT-CET

10 DAYS FREE DEMO

Attend Classes • Experience Our Teaching
Take Admission After Satisfaction
(No Hidden Conditions)

- ✓ 34+ Years of Academic Excellence
- ✓ Experienced & Dedicated Faculty
- ✓ Personal Attention
- ✓ Printed Notes & Regular Tests
- ✓ Strong Foundation for Boards & Competitive Exams

Santacruz Branch

101 Sai Chambers,
Opp. Santacruz Railway Station (East),
Near Depot, Santacruz (E), Mumbai 400055

Sion Branch

Opp. SIES College (Old),
Near Gaurahiga Hotel,
Sion (West), Mumbai

Limited Seats / Small Batch Size
CALL NOW: **7738007373**

डिजिटल क्रांति के दौर में बढ़ते साइबर अपराध, बड़ी चुनौती



-ललित गर्ग

डिजिटल क्रांति ने भारत को अभूतपूर्व गति, सुविधा और पारदर्शिता प्रदान की है। आज मोबाइल बैंकिंग, यूपीआई, ई-कॉमर्स, ऑनलाइन शिक्षा, डिजिटल स्वास्थ्य सेवाएं और कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) ने सामान्य नागरिक के जीवन को सरल और सक्रिय बनाया है। भारत विश्व की सबसे बड़ी डिजिटल अर्थव्यवस्थाओं में तेजी से उभर रहा है और हाइडिजिटल इंडिया तथा हाइकॉसिड भारत-2047 का सपना इसी तकनीकी परिवर्तन पर आधारित है। किंतु इस उजले परिदृश्य के समानांतर एक भयावह अंधेरा भी तेजी से फैल रहा है-साइबर अपराधों का बढ़ता साम्राज्य। डिजिटल अरेस्ट, ऑनलाइन गतिपथ ठगी, फिशिंग, पहचान की चोरी, निवेश घोटाले, व्यक्तिगत गोपनीयता पर संशय, सोशल मीडिया के माध्यम से अपराध, बाल यौन शोषण सामग्री का प्रसार और कृत्रिम बुद्धिमत्ता का दुरुपयोग आज केवल तकनीकी समस्या नहीं, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक स्थिरता और सामाजिक नैतिकता के लिए गंभीर चुनौती बन चुके हैं। विडंबना यह है कि जिस तकनीक का उद्देश्य मनुष्य के जीवन को सुरक्षित, सुविधाजनक और ज्ञानसमृद्ध बनाना था, वहीं तकनीक अपराधियों के लिए सबसे प्रभावी हथियार बनती जा रही है। इंटरनेट की असीम संभावनाओं का लाभ जितनी तेजी से समाज ने उठाया है, उतनी ही तेजी से अपराधियों ने भी उससे अपने हित में दाल लिया है। परिणामस्वरूप डिजिटल दुनिया में विश्वास का संकट गहराता जा रहा है। डिजिटल व्यवस्था को सबसे बड़ी पूंजी विश्वास है। जब कोई नागरिक मोबाइल पर व्हाट्सएप कोड स्कैन करता है, यूपीआई से भुगतान करता है या किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर निवेश करता है, तब वह केवल तकनीक पर नहीं, बल्कि पूरे डिजिटल तंत्र की विश्वसनीयता पर भरोसा करता है। यदि यही भरोसा लगातार अपराध ठगी, फर्जी कॉल, फिशिंग, नितांत व्यक्तिगत सूचनाओं के सार्वजनिक होने के भय, निवेश घोटालों और पहचान की चोरी जैसी घटनाओं से टूटने लगे, तो डिजिटल अर्थव्यवस्था की नींव कमजोर पड़ जाएगी। जिस प्रकार नकली मुद्रा का प्रसार पूरी आर्थिक व्यवस्था को संकट में डाल देता है, उसी प्रकार डिजिटल धोखाधड़ी का बढ़ना कैशलेस अर्थव्यवस्था की अवधारणा को कमजोर कर सकता है। परंपरागत अपराधों और साइबर अपराधों में मूलभूत अंतर है। पहले अपराध किसी निश्चित क्षेत्र तक सीमित रहते थे, अपराधी को अपराध और गिरफ्तारी की संभावना अपेक्षाकृत अधिक होती थी। आज साइबर अपराधी हजारों किलोमीटर दूर बैठकर कुछ ही मिनटों में लाखों लोगों तक पहुंच सकता है। उसके लिए जोखिम न्यूनतम और लाभ अधिकतम है। यही असंतुलन साइबर अपराध को अत्यंत खतरनाक बनाता है। अपराध का यह नया स्वरूप समाजसभ्यताओं, भाषाओं और कानूनों की पारंपरिक सीमाओं को भी चुनौती दे रहा है।

चिंता केवल आर्थिक अपराधों तक सीमित नहीं है। हाल के दिनों में सोशल मीडिया मंचों पर बच्चों के यौन शोषण से जुड़ी सामग्री के प्रचार-प्रसार के आरोपों ने पूरी दुनिया को झकझोर दिया है। यदि लोकप्रिय डिजिटल मंचों पर पैसे लेकर ऐसे विज्ञापन प्रसारित हो सकते हैं, तो यह केवल तकनीकी त्रुटि नहीं बल्कि नैतिक और सामाजिक विफलता भी है। प्रश्न यह भी है कि क्या सोशल मीडिया कंपनियों केवल स्वयं को तकनीकी मंच कहकर अपनी जिम्मेदारी से मुक्त हो सकती हैं? जब कृत्रिम बुद्धिमत्ता और एल्गोरिथ्म यह तय करते हैं कि कौन-सा विज्ञापन किस व्यक्ति तक पहुंचेगा, तब उन मंचों की जवाबदेही भी उतनी ही बड़ी हो जाती है। आज अनेक डिजिटल प्लेटफॉर्म आपत्तिजनक सामग्री हटाने का दावा करते हैं, किंतु व्यवहार में उनकी प्राथमिकता कई बार राजस्व और व्यावसायिक हित प्रतीत होती है। यदि बाल यौन शोषण, अश्लीलता, साइबर ठगी या संगठित अपराध से जुड़े विज्ञापन और सामग्री लंबे समय तक सक्रिय रह सकते हैं, तो यह केवल अपराधियों की सफलता नहीं, बल्कि डिजिटल मंचों की जवाबदेही पर भी गंभीर प्रश्नचिह्न है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और सामाजिक उत्तरदायित्व के बीच संतुलन बनाए बिना डिजिटल समाज स्वस्थ नहीं रह सकता। साइबर अपराध का सबसे दुखद पक्ष पीड़ित की मानसिक पीड़ा है। जीवनभर की बचत कुछ मिनटों में गायब हो जाती है। इसके बाद पुलिस, बैंक और साइबर हेल्पलाइन के चक्कर लगते हैं, लेकिन समय पर कार्रवाई नहीं होने के कारण अधिकांश मामलों में धन वापस नहीं मिल पाता। इससे नागरिक के भीतर विश्वास के प्रति अविश्वास पैदा होता है। यदि अपराधी को दंड न मिले और पीड़ित को राहत न मिले, तो कानून का भय भी समाप्त होने लगता है। भारत सरकार ने साइबर सुरक्षा को मजबूत करने के लिए अनेक कदम उठाए हैं। राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल, हेल्पलाइन, साइबर क्राइम समन्वय केंद्र तथा डिजिटल सुरक्षा संबंधी अनेक पहलें शुरू की गई हैं। न्यायपालिका ने भी ऑनलाइन धोखाधड़ी को आर्थिक सुरक्षा से जोड़कर गंभीर चिंता व्यक्त की है। फिर भी नीति और उसके प्रभावी क्रियान्वयन के बीच बड़ी दूरी दिखाई देती है। शिकायत दर्ज होने के बाद सुरक्षाती कुछ घंटे सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। यदि इसी अवधि में बैंक खाते फ्रीज कर दिए जाएं और धन के प्रवाह को रोक दिया जाए तो बड़ी राशि बचाई जा सकती है। लेकिन अक्सर कार्रवाई में देरी अपराधियों के पक्ष में चली जाती है।

डिजिटल सुरक्षा अब केवल पुलिस का विषय नहीं रही। यह आर्थिक नीति, राष्ट्रीय सुरक्षा, शिक्षा, प्रशासन और अंतरराष्ट्रीय सहयोग से जुड़ा बहुआयामी प्रश्न बन चुकी है। विकसित देशों ने साइबर सुरक्षा को राष्ट्रीय सुरक्षा के समान महत्व दिया है। विशेष एजेंसियां, अत्याधुनिक तकनीक, प्रशिक्षित विशेषज्ञ, रियल टाइम डेटा साझा करने की व्यवस्था और कठोर दंडात्मक कानून वहां की व्यवस्था का हिस्सा हैं। भारत को भी इसी दिशा में और अधिक सुदृढ़ कदम उठाने होंगे। स्थानीय पुलिस को डिजिटल फॉरेंसिक, ब्लॉकचेन विश्लेषण, कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित जांच और अंतरराष्ट्रीय साइबर कानूनों का प्रशिक्षण देना समय की आवश्यकता है। इसके साथ ही नागरिक जागरूकता की उतनी ही आवश्यकता है। तकनीक जितनी उन्नत होगी, अपराधी भी उतने ही नए तरीके खोजेंगे। इसलिए विद्यालयों, महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों और सामाजिक संगठनों के माध्यम से डिजिटल साक्षरता को जनआंदोलन बनाया जाना चाहिए। लोगों को संदिग्ध घंट, फर्जी कॉल, निवेश योजनाओं और सोशल मीडिया के छल-लपट से बचने का प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। किंतु यह भी उतना ही सत्य है कि सुरक्षा का पूरा दायित्व नागरिक पर डालकर सरकार, बैंक और डिजिटल कंपनियों अपनी जिम्मेदारी से मुक्त नहीं हो सकतीं। सुरक्षित डिजिटल वातावरण उपलब्ध कराना संस्थागत दायित्व है।

भ्रष्टाचार, लापरवाही और कमजोर केवाईसी व्यवस्था भी साइबर अपराध को बढ़ावा देती है। यदि फर्जी पहचान के आधार पर बैंक खाते खुलते हैं, यदि भुगतान प्लेटफॉर्म समय पर संचिध लेन-देन नहीं रोकेते, यदि आंतरिक मिलीभगत से अपराधियों को सुविधा मिलती है, तो यह केवल तकनीकी दोष नहीं बल्कि संस्थागत अपराध है। इसलिए पारदर्शी ऑडिट, कठोर उत्तरदायित्व और सख्त दंड व्यवस्था अनिवार्य होनी चाहिए। साइबर अपराध अब किसी एक देश की समस्या नहीं रहा। इंटरनेट की दुनिया में अपराधी सीमाओं से मुक्त हैं, इसलिए समाधान भी वैश्विक होना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र सहित विश्व की प्रमुख शक्तियों को साइबर अपराधों के विरुद्ध साझा कानूनी ढांचा, त्वरित सूचना आदान-प्रदान और तकनीकी सहयोग विकसित करना होगा। जिस प्रकार आतंकवाद के विरुद्ध वैश्विक सहयोग आवश्यक माना गया, उसी प्रकार साइबर अपराधों के विरुद्ध भी विश्वव्यापी समन्वय समय की मांग है। अंतर: डिजिटल क्रांति का वास्तविक उद्देश्य केवल तकनीकी प्रगति नहीं, बल्कि मानव जीवन को अधिक सुरक्षित, समृद्ध और सम्मानजनक बनाना है। यदि यही क्रांति भय, असुरक्षा और अविश्वास का कारण बनने लगे, तो उसकी सफलता अधूरी रह जाएगी। डिजिटल भारत की वास्तविक शक्ति उसके ऐस, सर्वरों और आंकड़ों में नहीं, बल्कि उस विश्वास में निहित है, जिसके साथ करोड़ों नागरिक प्रतिदिन अपने मोबाइल पर एक-एक लेन-देन करते हैं। आज आवश्यकता केवल तकनीकी समाधान नहीं हैं, बल्कि तकनीकी, नैतिकता, कानून और उत्तरदायित्व के समन्वित मॉडल की है। सरकार को कठोर कानून, त्वरित न्याय और सक्षम जांच तंत्र विकसित करना होगा, डिजिटल कंपनियों को अपने सामाजिक दायित्व का निर्वहन करना होगा, वित्तीय संस्थानों को सुरक्षा और जवाबदेही बढ़ानी होगी और नागरिकों को डिजिटल जीवनशैली के बीच संतुलन हाथों ही विकसित भारत की सबसे बड़ी कसौटी है। यदि यह संतुलन स्थापित हो गया, तो डिजिटल भारत विश्व का सबसे विश्वसनीय डिजिटल लोकतंत्र बन सकता है, अन्यथा तकनीकी उपलब्धियां भी अविश्वास के बोझ तले दम तोड़ देंगी।

वैश्विक कूटनीति के केंद्र में भारत-मोदी की विदेश यात्राओं का वास्तविक हासिल



अशोक भाटिया

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 से 11 जुलाई 2026 तक इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की आधिकारिक विदेश यात्रा पर गए हैं। इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य तीनों देशों के साथ रणनीतिक साझेदारी, व्यापार और आर्थिक संबंधों को मजबूत करना है। विरोधी दल भले ही इसे फिजूल खर्ची बता रहे हो पर नरेंद्र मोदी की लगातार विदेश यात्राओं का उद्देश्य भारत के लिए रणनीतिक और आर्थिक लाभ सुनिश्चित करना है, जिससे अंतरराष्ट्रीय व्यापार, ऊर्जा सुरक्षा, रक्षा सहयोग और तकनीकी आदान-प्रदान को बढ़ावा मिला है। इन यात्राओं के माध्यम से प्रमुख विदेशी कंपनियों से भारी निवेश आने से देश में रोजगार के अवसर बढ़ते हैं और वैश्विक मंच पर भारत की साख व कूटनीतिक पकड़ मजबूत होती है। साथ ही, इन दौरों के जरिए प्रवासी भारतीयों के हितों की रक्षा भी की जाती है। देखने वाली बात यह है कि वैश्वीकरण के इस दौर में किसी भी देश की प्रगति उसकी आंतरिक नीतियों के साथ-साथ इस बात पर भी निर्भर करती है कि वैश्विक पटल पर उसके संबंध कैसे हैं। पिछले एक दशक में भारत की विदेश नीति में एक अभूतपूर्व गतिशीलता देखी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लगातार

समझौतों ने भारतीय निर्यातकों के लिए नए रास्ते खोले हैं, जिससे कपड़ा, रत्न-आभूषण और कृषि उत्पादों के व्यापार को सीधा लाभ मिला है। शीत युद्ध के दौर की पुरानी रक्षात्मक विदेश नीति को छोड़कर भारत ने अब 'बहु-पक्षीय संरक्षण' की नीति अपनाई है। प्रधानमंत्री मोदी की व्यक्तिगत कूटनीति ने भारत को वैश्विक महाशक्तियों के बीच एक अनूठा और संतुलित स्थान दिलाया है। इन विदेश यात्राओं के क्षेत्र में भारी दबाव के बावजूद, प्रधानमंत्री मोदी की रूस यात्राओं और 'क्वाड' शिखर सम्मेलनों के माध्यम से भारत ने भारत-प्रशांत क्षेत्र में अपनी सुरक्षा चिंताओं को मजबूती से रेखांकित किया है। रक्षा कूटनीति के तहत अमेरिका के साथ महत्वपूर्ण और उभरती प्रौद्योगिकियों पर पहल जैसे समझौते होंगे। पश्चिमी देशों के भारी दबाव के बावजूद, प्रधानमंत्री मोदी की रूस यात्राओं और राष्ट्रपति पुतिन के साथ उनके मजबूत संबंधों ने यह सुनिश्चित किया कि भारत को संकट के समय में भी रियायती दरों पर कच्चे तेल की निर्बाध आपूर्ति मिलती रहे। यह भारत की रणनीतिक स्वयत्तता की एक बड़ी जीत है। पड़ोस पहले की नीति: खाड़ी देशों (यूएई, सऊदी अरब) के साथ संबंधों का कायाकल्प इस कूटनीति की सबसे बड़ी सफलताओं में से एक है। कभी पाकिस्तान के करीब माने जाने वाले ये देश आज भारत के सबसे बड़े व्यापारिक और रणनीतिक साझेदार बनकर उभरे हैं। देखा जाय तो एक तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था होने के नाते, भारत की ऊर्जा जरूरतें विशाल हैं। प्रधानमंत्री की विदेश यात्राओं ने भारत की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने में केंद्रीय भूमिका निभाई है। खाड़ी देशों, रूस

और अफ्रीकी देशों के दौरों ने भारत के लिए ऊर्जा के स्रोतों विविधीकरण किया है, जिससे देश वैश्विक बाजार में तेल की कीमतों के उतार-चढ़ाव से काफी हद तक सुरक्षित हुआ है। फ्रांस के साथ मिलकर 'अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन' की स्थापना और ब्रिटेन के साथ 'वन सन, वन वर्ल्ड, वन ग्रिड' की पहल ने भारत को वैश्विक जलवायु कूटनीति के नेतृत्वकर्ता के रूप में स्थापित किया है। इससे देश में नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में भारी विदेशी निवेश और तकनीक का आगमन हुआ है। आज तक भारत ऐतिहासिक रूप से अपनी रक्षा जरूरतों के लिए दूसरे देशों पर निर्भर रहा है। मोदी जी की विदेश यात्राओं ने इस निर्भरता के स्वरूप को बदला है। अब भारत केवल एक 'खरीदार' नहीं, बल्कि 'सह-उत्पादक' बनने की दिशा में अग्रसर है। फ्रांस से राफेल विमानों की खरीद हो या अमेरिका के साथ जीई फाइटर जेट इंजनों के भारत में निर्माण का समझौता, इन सभी में भारत के भीतर तकनीकी हस्तान्तरण की शक्तों को प्राथमिकता दी गई है। ताइवान, जापान और अमेरिका के साथ हुए समझौतों के माध्यम से भारत को सेमीकंडक्टर डिजाइन और विनिर्माण का एक नया वैश्विक केंद्र बनाने की नींव रखी गई है। इसके अतिरिक्त, भारत के डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर (UPI) को सिंगापुर, यूएई और कई यूरोपीय देशों में स्वीकार्यता मिलाना भारतीय तकनीक की वैश्विक धाक को दर्शाता है। लगातार दौरों और व्यक्तिगत संपर्क के कारण वैश्विक मंचों पर भारत का वजन काफी बढ़ गया है। भारत को अब अंतरराष्ट्रीय समस्याओं के हिस्से के रूप में नहीं, बल्कि उनके समाधान के रूप में देखा जाता है। भारत को जी-20 अध्यक्षता की सफलता और उसमें 'ग्लोबल साउथ' (विकासशील देशों) की आवाज को बुलंद करना प्रधानमंत्री की वैश्विक स्वीकार्यता का ही परिणाम था। अफ्रीकी संघ को जी-20 का स्थायी सदस्य बनवाना भारत की कूटनीतिक कुशलता का प्रमाण है। संयुक्त राष्ट्र में 21 जून को 'अंतरराष्ट्रीय योग दिवस' के रूप में मान्यता दिलाया, वैश्विक स्तर पर आयुर्वेद का प्रचार और दुनिया के विभिन्न देशों में 'महान भारतीय प्रवासियों' की देश की प्रगति से जोड़ना-इन सबने भारत की सांस्कृतिक साख को अत्यधिक मजबूत किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी हर विदेश यात्रा में वहां रहने वाले भारतीय समुदाय सीधे संबन्ध की एक नई परंपरा शुरू की। मैडिसन स्क्वायर से लेकर सिडनी और दुबई के स्टेडियमों तक, प्रवासी भारतीयों के साथ इन मुलाकातों के गहरे कूटनीतिक मायने हैं। आज विदेशों में बैठे भारतीय वहां की सरकारों की नीतियों को भारत के पक्ष में प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं। मजबूत अंतरराष्ट्रीय संबंधों के कारण ही भारत संकटग्रस्त क्षेत्रों से अपने नागरिकों को सुरक्षित निकालने में हमेशा सफल रहा है। चाहे यूक्रेन युद्ध के दौरान 'ऑपरेशन गंगा' हो, सूडान से 'ऑपरेशन कावेरी' हो, या कोविड के समय 'वंदे भारत मिशन'-वैश्विक नेताओं से प्रधानमंत्री के सीधे संपर्कों ने इन ऑपरेशनों को सुगम बनाया। यद्यपि इन यात्राओं के लाभ बहुआयामी हैं, लेकिन एक संतुलित संपादकीय के नाते इसके दूसरे पहलू को भी देखा होगा। कूटनीति में केवल

सूखती धरती, बढ़ती प्यास : जल दिवालियापन की ओर बढ़ता भारत



- डॉ. सत्यवान सौरभ

जल केवल एक प्राकृतिक संसाधन नहीं, बल्कि जीवन, सभ्यता, आर्थिक विकास, खाद्य सुरक्षा और पर्यावरणीय संतुलन का आधार है। मानव इतिहास की अधिकांश महान सभ्यताएँ नदियों के किनारे विकसित हुईं, क्योंकि जल ही जीवन और समृद्धि का मूल स्रोत रहा है। किंतु इस्वीकीसवीं शताब्दी में जल संसाधनों पर बढ़ते दबाव ने विश्व के अनेक देशों के समक्ष गंभीर संकट उत्पन्न कर दिया है। भारत इस तंत्र का सबसे बड़ा उदाहरण बनकर उभर रहा है। विश्व की लगभग 18 प्रतिशत जनसंख्या का भार वहन करने वाला भारत विश्व के केवल लगभग 4 प्रतिशत मीठे जल संसाधनों का स्वामी है। बढ़ती जनसंख्या, तीव्र शहरीकरण, औद्योगिकीकरण, कृषि क्षेत्र में जल का अत्यधिक दोहन, जल प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन तथा जल प्रबंधन की संरचनात्मक कमियों ने देश को ऐसी स्थिति में पहुंचा दिया है जहाँ केवल जल संकट से आगे बढ़कर पर्याप्त नहीं रह गया है। अनेक विशेषज्ञों का मत है कि यदि वर्तमान प्रवृत्तियाँ जारी रहें तो भारत जल संकट से जगो बंधकर जल दिवालियापन की स्थिति में पहुँच सकता है। जल दिवालियापन वह अवस्था है जब उपलब्ध जल संसाधन प्राकृतिक पुनर्भरण की क्षमता से अधिक दोहन के कारण समाप्तप्राय हो जाएँ, जल की गुणवत्ता इतनी खराब हो जाए कि उसका उपयोग कठिन हो जाए तथा समाज, कृषि, उद्योग और पारिस्थितिकी की आवश्यकताओं की पूर्ति संभव न रह जाए। भारत में प्रति व्यक्ति वार्षिक जल उपलब्धता स्वतंत्रता के प्रारंभिक वर्षों में पाँच हजार घन मीटर से अधिक थी, जो लगातार घटते-घटते जल तनाव की सीमा के निकट पहुँच चुकी है। अनेक महानगर समय-समय पर पेयजल संकट का सामना कर चुके हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में भूजल स्तर निरंतर नीचे जा रहा है। अनेक नदियाँ प्रदूषण के कारण जीवनदायिनी के बजाय प्रदूषण वाहक बनती जा रही हैं। वर्षों की अनिश्चितता और जलवायु परिवर्तन ने स्थिति को और जटिल बना दिया है। यह संकट केवल प्राकृतिक कारणों से



महत्वपूर्ण कारण है। भारत के कुल मीठे जल का लगभग अस्सी प्रतिशत भाग कृषि में प्रयुक्त होता है, किंतु सिंचाई की दक्षता अभी भी निम्न है। अधिकांश क्षेत्रों में पारंपरिक बाढ़ सिंचाई पद्धति अपनाई जाती है, जिसमें बड़ी मात्रा में जल व्यर्थ बह जाता है। न्यूनतम समर्थन मूल्य तथा सरकारी खरीद की नीतियों ने कई राज्यों में धान और गन्ने जैसी अत्यधिक जल-आवश्यक फसलों की खेती को प्रोत्साहित किया है, जबकि उन क्षेत्रों की जल उपलब्धता इसके अनुकूल नहीं है। इससे भूजल पर अतिरिक्त दबाव पड़ता है और दीर्घकाल में कृषि की स्थिरता भी प्रभावित होती है। शहरी जल प्रबंधन भी गंभीर कमियों से ग्रस्त है। तेजी से बढ़ते शहरों में पाइपलाइन से जल की भारी हानि होती है। गैर-राजस्व जल की मात्रा कई नगरों में अत्यधिक है। उपचारित अपशिष्ट जल का पुनः उपयोग बहुत कम किया जाता है। झीलों और तालाबों पर अतिक्रमण होने से वर्षा जल का प्राकृतिक संचयन समाप्त हो रहा है। विडंबना यह है कि एक ओर शहरों में वर्षा के समय जलभराव होता है और दूसरी ओर गर्मियों में वही शहर जल संकट से जूझते हैं। यह दर्शाता है कि हमारी जल प्रबंधन प्रणाली प्राकृतिक जल चक्र के अनुरूप विकसित नहीं हो सकी है। जल प्रबंधन की एक अन्य संरचनात्मक कमजोरी संस्थागत विखंडन है। जल से संबंधित कार्य अनेक मंत्रालयों, विभागों और एजेंसियों में विभाजित हैं। सिंचाई, पेयजल, भूजल, नदी संरक्षण, शहरी जलापूर्ति और पर्यावरण संरक्षण अलग-अलग संस्थाओं के अधीन हैं। इनके बीच समन्वय का अभाव समेकित जल नीति निर्माण और प्रभावी क्रियान्वयन में बाधा उत्पन्न करता है। नदी बेसिन आधारित योजनाओं के आधार पर जल प्रबंधन किया जाता है, जिससे संसाधनों का वैज्ञानिक उपयोग नहीं हो पाता। जलवायु परिवर्तन ने इस

संकट को और गहरा बना दिया है। मानसून की अनिश्चितता, अल्प अवधि में अत्यधिक वर्षा, लंबे शुष्क काल, हिमालयी हिमनदों के पिघलने तथा तापमान वृद्धि ने जल चक्र को प्रभावित किया है। इससे बाढ़ और सूखे दोनों की आवृत्ति तथा तीव्रता बढ़ी है। जल संसाधनों की योजना यदि पुराने जलवायु पैटर्न के आधार पर बनाई जाएगी तो भविष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति संभव नहीं होगी। इन सभी चुनौतियों के कारण जल संकट केवल संसाधन संबंधी समस्या नहीं रह गया है, बल्कि यह खाद्य सुरक्षा, ऊर्जा सुरक्षा, सर्वांगिक स्वास्थ्य, आर्थिक विकास, सामाजिक स्थिरता और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा व्यापक प्रश्न बन चुका है। जल की कमी से कृषि उत्पादन प्रभावित होगा, जिससे खाद्यान्न सुरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। उद्योगों की उत्पादन क्षमता घट सकती है। जलजनित रोगों का प्रसार बढ़ सकता है। राज्यों और क्षेत्रों के बीच जल विवाद तीव्र हो सकते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों से बड़े पैमाने पर पलायन होने की संभावना भी बढ़ सकती है। अतः जल सुरक्षा को राष्ट्रीय विकास की केंद्रीय प्राथमिकता बनाना समय की आवश्यकता है। इस चुनौती का समाधान केवल नए बौद्धि बनाने या अधिक भूजल निकालने से संभव नहीं है। इसके लिए जल प्रबंधन की संपूर्ण सोच में परिवर्तन आवश्यक है। सबसे पहले जल को एक सीमित और मूल्यवान प्राकृतिक संपदा के रूप में स्वीकार करना होगा। जल संसाधनों का प्रबंधन नदी बेसिन आधारित समेकित दृष्टिकोण से किया जाना चाहिए, जिसमें स्थानीय प्राथमिकता के साथ फसल जल प्रवाहों को प्रोत्साहन दिया जाए तथा फसल विविधीकरण को बढ़ावा मिले। न्यूनतम समर्थन मूल्य और कृषि प्रोत्साहनों को जल संरक्षण के लिए जल प्रबंधन की संपूर्ण सोच में परिवर्तन आवश्यक है। सबसे पहले जल को एक सीमित और मूल्यवान प्राकृतिक संपदा के रूप में स्वीकार करना होगा। जल संसाधनों का प्रबंधन नदी बेसिन आधारित समेकित दृष्टिकोण से किया जाना चाहिए, जिसमें स्थानीय प्राथमिकता के साथ फसल जल प्रवाहों को प्रोत्साहन दिया जाए तथा फसल विविधीकरण को बढ़ावा मिले। न्यूनतम समर्थन मूल्य और कृषि प्रोत्साहनों को जल संरक्षण के लिए जल प्रबंधन की संपूर्ण सोच में परिवर्तन आवश्यक है। सबसे पहले जल को एक सीमित और मूल्यवान प्राकृतिक संपदा के रूप में स्वीकार करना होगा। जल संसाधनों का प्रबंधन नदी बेसिन आधारित समेकित दृष्टिकोण से किया जाना चाहिए, जिसमें स्थानीय प्राथमिकता के साथ फसल जल प्रवाहों को प्रोत्साहन दिया जाए तथा फसल विविधीकरण को बढ़ावा मिले। न्यूनतम समर्थन मूल्य और कृषि प्रोत्साहनों को जल संरक्षण के लिए जल प्रबंधन की संपूर्ण सोच में परिवर्तन आवश्यक है। सबसे पहले जल को एक सीमित और मूल्यवान प्राकृतिक संपदा के रूप में स्वीकार करना होगा। जल संसाधनों का प्रबंधन नदी बेसिन आधारित समेकित दृष्टिकोण से किया जाना चाहिए, जिसमें स्थानीय प्राथमिकता के साथ फसल जल प्रवाहों को प्रोत्साहन दिया जाए तथा फसल विविधीकरण को बढ़ावा मिले। न्यूनतम समर्थन मूल्य और कृषि प्रोत्साहनों को जल संरक्षण के लिए जल प्रबंधन की संपूर्ण सोच में परिवर्तन आवश्यक है। सबसे पहले जल को एक सीमित और मूल्यवान प्राकृतिक संपदा के रूप में स्वीकार करना होगा। जल संसाधनों का प्रबंधन नदी बेसिन आधारित समेकित दृष्टिकोण से किया जाना चाहिए, जिसमें स्थानीय प्राथमिकता के साथ फसल जल प्रवाहों को प्रोत्साहन दिया जाए तथा फसल विविधीकरण को बढ़ावा मिले। न्यूनतम समर्थन मूल्य और कृषि प्रोत्साहनों को जल संरक्षण के लिए जल प्रबंधन की संपूर्ण सोच में परिवर्तन आवश्यक है। सबसे पहले जल को एक सीमित और मूल्यवान प्राकृतिक संपदा के रूप में स्वीकार करना होगा। जल संसाधनों का प्रबंधन नदी बेसिन आधारित समेकित दृष्टिकोण से किया जाना चाहिए, जिसमें स्थानीय प्राथमिकता के साथ फसल जल प्रवाहों को प्रोत्साहन दिया जाए तथा फसल विविधीकरण को बढ़ावा मिले। न्यूनतम समर्थन मूल्य और कृषि प्रोत्साहनों को जल संरक्षण के लिए जल प्रबंधन की संपूर्ण सोच में परिवर्तन आवश्यक है। सबसे पहले जल को एक सीमित और मूल्यवान प्राकृतिक संपदा के रूप में स्वीकार करना होगा। जल संसाधनों का प्रबंधन नदी बेसिन आधारित समेकित दृष्टिकोण से किया जाना चाहिए, जिसमें स्थानीय प्राथमिकता के साथ फसल जल प्रवाहों को प्रोत्साहन दिया जाए तथा फसल विविधीकरण को बढ़ावा मिले। न्यूनतम समर्थन मूल्य और कृषि प्रोत्साहनों को जल संरक्षण के लिए जल प्रबंधन की संपूर्ण सोच में परिवर्तन आवश्यक है। सबसे पहले जल को एक सीमित और मूल्यवान प्राकृतिक संपदा के रूप में स्वीकार करना होगा। जल संसाधनों का प्रबंधन नदी बेसिन आधारित समेकित दृष्टिकोण से किया जाना चाहिए, जिसमें स्थानीय प्राथमिकता के साथ फसल जल प्रवाहों को प्रोत्साहन दिया जाए तथा फसल विविधीकरण को बढ़ावा मिले। न्यूनतम समर्थन मूल्य और कृषि प्रोत्साहनों को जल संरक्षण के लिए जल प्रबंधन की संपूर्ण सोच में परिवर्तन आवश्यक है। सबसे पहले जल को एक सीमित और मूल्यवान प्राकृतिक संपदा के रूप में स्वीकार करना होगा। जल संसाधनों का प्रबंधन नदी बेसिन आधारित समेकित दृष्टिकोण से किया जाना चाहिए, जिसमें स्थानीय प्राथमिकता के साथ फसल जल प्रवाहों को प्रोत्साहन दिया जाए तथा फसल विविधीकरण को बढ़ावा मिले। न्यूनतम समर्थन मूल्य और कृषि प्रोत्साहनों को जल संरक्षण के लिए जल प्रबंधन की संपूर्ण सोच में परिवर्तन आवश्यक है। सबसे पहले जल को एक सीमित और मूल्यवान प्राकृतिक संपदा के रूप में स्वीकार करना होगा। जल संसाधनों का प्रबंधन नदी बेसिन आधारित समेकित दृष्टिकोण से किया जाना चाहिए, जिसमें स्थानीय प्राथमिकता के साथ फसल जल प्रवाहों को प्रोत्साहन दिया जाए तथा फसल विविधीकरण को बढ़ावा मिले। न्यूनतम समर्थन मूल्य और कृषि प्रोत्साहनों को जल संरक्षण के लिए जल प्रबंधन की संपूर्ण सोच में परिवर्तन आवश्यक है। सबसे पहले जल को एक सीमित और मूल्यवान प्राकृतिक संपदा के रूप में स्वीकार करना होगा। जल संसाधनों का प्रबंधन नदी बेसिन आधारित समेकित दृष्टिकोण से किया जाना चाहिए, जिसमें स्थानीय प्राथमिकता के साथ फसल जल प्रवाहों को प्रोत्साहन दिया जाए तथा फसल विविधीकरण को बढ़ावा मिले। न्यूनतम समर्थन मूल्य और कृषि प्रोत्साहनों को जल संरक्षण के लिए जल प्रबंधन की संपूर्ण सोच में परिवर्तन आवश्यक है। सबसे पहले जल को एक सीमित और मूल्यवान प्राकृतिक संपदा के रूप में स्वीकार करना होगा। जल संसाधनों का प्रबंधन नदी बेसिन आधारित समेकित दृष्टिकोण से किया जाना चाहिए, जिसमें स्थानीय प्राथमिकता के साथ फसल जल प्रवाहों को प्रोत्साहन दिया जाए तथा फसल विविधीकरण को बढ़ावा मिले। न्यूनतम समर्थन मूल्य और कृषि प्रोत्साहनों को जल संरक्षण के लिए जल प्रबंधन की संपूर्ण सोच में परिवर्तन आवश्यक है। सबसे पहले जल को एक सीमित और मूल्यवान प्राकृतिक संपदा के रूप में स्वीकार करना होगा। जल संसाधनों का प्रबंधन नदी बेसिन आधारित समेकित दृष्टिकोण से किया जाना चाहिए, जिसमें स्थानीय प्राथमिकता के साथ फसल जल प्रवाहों को प्रोत्साहन दिया जाए तथा फसल विविधीकरण को बढ़ावा मिले। न्यूनतम समर्थन मूल्य और कृषि प्रोत्साहनों को जल संरक्षण के लिए जल प्रबंधन की संपूर्ण सोच में परिवर्तन आवश्यक है। सबसे पहले जल को एक सीमित और मूल्यवान प्राकृतिक संपदा के रूप में स्वीकार करना होगा। जल संसाधनों का प्रबंधन नदी बेसिन आधारित समेकित दृष्टिकोण से किया जाना चाहिए, जिसमें स्थानीय प्राथमिकता के साथ फसल जल प्रवाहों को प्रोत्साहन दिया जाए तथा फसल विविधीकरण को बढ़ावा मिले। न्यूनतम समर्थन मूल्य और कृषि प्रोत्साहनों को जल संरक्षण के लिए जल प्रबंधन की संपूर्ण सोच में परिवर्तन आवश्यक है। सबसे पहले जल को एक सीमित और मूल्यवान प्राकृतिक संपदा के रूप में स्वीकार करना होगा। जल संसाधनों का प्रबंधन नदी बेसिन आधारित समेकित दृष्टिकोण से किया जाना चाहिए, जिसमें स्थानीय प्राथमिकता के साथ फसल जल प्रवाहों को प्रोत्साहन दिया जाए तथा फसल विविधीकरण को बढ़ावा मिले। न्यूनतम समर्थन मूल्य और कृषि प्रोत्साहनों को जल संरक्षण के लिए जल प्रबंधन की संपूर्ण सोच में परिवर्तन आवश्यक है। सबसे पहले जल को एक सीमित और मूल्यवान प्राकृतिक संपदा के रूप में स्वीकार करना होगा। जल संसाधनों का प्रबंधन नदी बेसिन आधारित समेकित दृष्टिकोण से किया जाना चाहिए, जिसमें स्थानीय प्राथमिकता के साथ फसल जल प्रवाहों को प्रोत्साहन दिया जाए तथा फसल विविधीकरण को बढ़ावा मिले। न्यूनतम समर्थन मूल्य और कृषि प्रोत्साहनों को जल संरक्षण के लिए जल प्रबंधन की संपूर्ण सोच में परिवर्तन आवश्यक है। सबसे पहले जल को एक सीमित और मूल्यवान प्राकृतिक संपदा के रूप में स्वीकार करना होगा। जल संसाधनों का प्रबंधन नदी बेसिन आधारित समेकित दृष्टिकोण से किया जाना चाहिए, जिसमें स्थानीय प्राथमिकता के साथ फसल जल प्रवाहों को प्रोत्साहन दिया जाए तथा फसल विविधीकरण को बढ़ावा मिले। न्यूनतम समर्थन मूल्य और कृषि प्रोत्साहनों को जल संरक्षण के लिए जल प्रबंधन की संपूर्ण सोच में परिवर्तन आवश्यक है। सबसे पहले जल को एक सीमित और मूल्यवान प्राकृतिक संपदा के रूप में स्वीकार करना होगा। जल संसाधनों का प्रबंधन नदी बेसिन आधारित समेकित दृष्टिकोण से किया जाना चाहिए, जिसमें स्थानीय प्राथमिकता के साथ फसल जल प्रवाहों को प्रोत्साहन दिया जाए तथा फसल विविधीकरण को बढ़ावा मिले। न्यूनतम समर्थन मूल्य और कृषि प्रोत्साहनों को जल संरक्षण के लिए जल प्रबंधन की संपूर्ण सोच में परिवर्तन आवश्यक है। सबसे पहले जल को एक सीमित और मूल्यवान प्राकृतिक संपदा के रूप में स्वीकार करना होगा। जल संसाधनों का प्रबंधन नदी बेसिन आधारित समेकित दृष्टिकोण से किया जाना चाहिए, जिसमें स्थानीय प्राथमिकता के साथ फसल जल प्रवाहों को प्रोत्साहन दिया जाए तथा फसल विविधीकरण को बढ़ावा मिले। न्यूनतम समर्थन मूल्य और कृषि प्रोत्साहनों को जल संरक्षण के लिए जल प्रबंधन की संपूर्ण सोच में परिवर्तन आवश्यक है। सबसे पहले जल को एक सीमित और मूल्यवान प्राकृतिक संपदा के रूप में स्वीकार करना होगा। जल संसाधनों का प्रबंधन नदी बेसिन आधारित समेकित दृष्टिकोण से किया जाना चाहिए, जिसमें स्थानीय प्राथमिकता के साथ फसल जल प्रवाहों को प्रोत्साहन दिया जाए तथा फसल विविधीकरण को बढ़ावा मिले। न्यूनतम समर्थन मूल्य और कृषि प्रोत्साहनों को जल संरक्षण के लिए जल प्रबंधन की संपूर्ण सोच में परिवर्तन आवश्यक है। सबसे पहले जल को एक सीमित और मूल्यवान प्राकृतिक संपदा के रूप में स्वीकार करना होगा। जल संसाधनों का प्रबंधन नदी बेसिन आधारित समेकित दृष्टिकोण से किया जाना चाहिए, जिसमें स्थानीय प्राथमिकता के साथ फसल जल प्रवाहों को प्रोत्साहन दिया जाए तथा फसल विविधीकरण को बढ़ावा मिले। न्यूनतम समर्थन मूल्य और कृषि प्रोत्साहनों को जल संरक्षण के लिए जल प्रबंधन की संपूर्ण सोच में परिवर्तन आवश्यक है। सबसे पहले जल को एक सीमित और मूल्यवान प्राकृतिक संपदा के रूप में स्वीकार करना होगा। जल संसाधनों का प्रबंधन नदी बेसिन आधारित समेकित दृष्टिकोण से किया जाना चाहिए, जिसमें स्थानीय प्राथमिकता के साथ फसल जल प्रवाहों को प्रोत्साहन दिया जाए तथा फसल विविधीकरण को बढ़ावा मिले। न्यूनतम समर्थन मूल्य और कृषि प्रोत्साहनों को जल संरक्षण के लिए जल प्रबंधन की संपूर्ण सोच में परिवर्तन आवश्यक है। सबसे पहले जल को एक सीमित और मूल्यवान प्राकृतिक संपदा के रूप में स्वीकार करना होगा। जल संसाधनों का प्रबंधन नदी बेसिन आधारित समेकित दृष्टिकोण से किया जाना चाहिए, जिसमें स्थानीय प्राथमिकता के साथ फसल जल प्रवाहों को प्रोत्साहन दिया जाए तथा फसल विविधीकरण को बढ़ावा मिले। न्यूनतम समर्थन मूल्य और कृषि प्रोत्साहनों को जल संरक्षण के लिए जल प्रबंधन की संपूर्ण सोच में परिवर्तन आवश्यक है। सबसे पहले जल को एक सीमित और मूल्यवान प्राकृतिक संपदा के रूप में स्वीकार करना होगा। जल संसाधनों का प्रबंधन नदी बेसिन आधारित समेकित दृष्टिकोण से किया जाना चाहिए, जिसमें स्थानीय प्राथमिकता के साथ फसल जल प्रवाहों को प्रोत्साहन दिया जाए तथा फसल विविधीकरण को बढ़ावा मिले। न्यूनतम समर्थन मूल्य और कृषि प्रोत्साहनों को जल संरक्षण के लिए जल प्रबंधन की संपूर्ण सोच में परिवर्तन आवश्यक है। सबसे पहले जल को एक सीमित और मूल्यवान प्राकृतिक संपदा के रूप में स्वीकार करना होगा। जल संसाधनों का प्रबंधन नदी बेसिन आधारित समेकित दृष्टिकोण से किया जाना चाहिए, जिसमें स्थानीय प्राथमिकता के साथ फसल जल प्रवाहों को प्रोत्साहन दिया जाए तथा फसल विविधीकरण को बढ़ावा मिले। न्यूनतम समर्थन मूल्य और कृषि प्रोत्साहनों को जल संरक्षण के लिए जल प्रबंधन की संपूर्ण सोच में परिवर्तन आवश्यक है। सबसे पहले जल को एक सीमित और मूल्यवान प्राकृतिक संपदा के रूप में स्वीकार करना होगा। जल संसाधनों का प्रबंधन नदी बेसिन आधारित समेकित दृष्टिकोण से किया जाना चाहिए, जिसमें स्थानीय प्राथमिकता के साथ फसल जल प्रवाहों को प्रोत्साहन दिया जाए तथा फसल विविधीकरण को बढ़ावा मिले। न्यूनतम समर्थन मूल्य और कृषि प्रोत्साहनों को जल संरक्षण के लिए जल प्रबंधन की संपूर्ण सोच में परिवर्तन आवश्यक है। सबसे पहले जल को एक सीमित और मूल्यवान प्राकृतिक संपदा के रूप में स्वीकार करना होगा। जल संसाधनों का प्रबंधन नदी बेसिन आधारित समेकित दृष्टिकोण से किया जाना चाहिए, जिसमें स्थानीय प्राथमिकता के साथ फसल जल प्रवाहों को प्रोत्साहन दिया जाए तथा फसल विविधीकरण को बढ़ावा मिले। न्यूनतम समर्थन मूल्य और कृषि प्रोत्साहनों को जल संरक्षण के लिए जल प्रबंधन की संपूर्ण सोच में परिवर्तन आवश्यक है। सबसे पहले जल को एक सीमित और मूल्यवान प्राकृतिक संपदा के रूप में स्वीकार करना होगा। जल संसाधनों का प्रबंधन नदी बेसिन आधारित समेकित दृष्टिकोण से किया जाना चाहिए, जिसमें स्थानीय प्राथमिकता के साथ फसल जल प्रवाहों को प्रोत्साहन दिया जाए तथा फसल विविधीकरण को बढ़ावा मिले। न्यूनतम समर्थन मूल्य और कृषि प्रोत्साहनों को जल संरक्षण के लिए जल प्रबंधन की संपूर्ण सोच में परिवर्तन आवश्यक है। सबसे पहले जल को एक सीमित और मूल्यवान प्राकृतिक संपदा के रूप में स्वीकार करना होगा। जल संसाधनों का प्रबंधन नदी बेसिन आधारित समेकित दृष्टिकोण से किया जाना चाहिए, जिसमें स्थानीय प्राथमिकता के साथ फसल जल प्रवाहों को प्रोत्साहन दिया जाए तथा फसल विविधीकरण को बढ़ावा मिले। न्यूनतम समर्थन मूल्य और कृषि प्रोत्साहनों को जल संरक्षण के लिए जल प्रबंधन की संपूर्ण सोच में परिवर्तन आवश्यक है। सबसे पहले जल को एक सीमित और मूल्यवान प्राकृतिक संपदा के रूप में स्वीकार करना होगा। जल संसाधनों का प्रबंधन नदी बेसिन आधारित समेकित दृष्टिकोण से किया जाना चाहिए, जिसमें स्थानीय प्राथमिकता के साथ फसल जल प्रवाहों को प्रोत्साहन दिया जाए तथा फसल विविधीकरण को बढ़ावा मिले। न्यूनतम समर्थन मूल्य और कृषि प्रोत्साहनों को जल संरक्षण के लिए जल प्र

नारपोली में शिवसेना नेता संजय भोईर के जनसंपर्क कार्यालय का भव्य उद्घाटन समारोह, जनसेवा को मिलेगी नई दिशा



भिवंडी (उत्तरशक्ति)। नारपोली स्थित साईंप्रसन सोसायटी, नारपोली पुलिस स्टेशन के समीप भिवंडी मनापा के नगरसेवक एवं शिवसेना उपशहर प्रमुख संजय (संदीप) गणपत भोईर के नए जनसंपर्क कार्यालय का उद्घाटन समारोह उत्साहपूर्ण माहौल में संपन्न हुआ। समारोह में क्षेत्र के नागरिकों और शिवसेना पदाधिकारियों की बड़ी संख्या में उपस्थिति रही। इस अवसर पर विधायक महेश चौधरी, पूर्व विधायक रूपेश म्हात्रे, शिवसेना जिल्हाप्रमुख देवानंद थले, गटनेता मनोज काटेकर, पूर्व शिक्षण मंडल नगरसेवक संतोष शेठे, सुंदर नाइक, शहरप्रमुख संजय काबुकर तथा युवासेना भिवंडी पश्चिम विधानसभा अध्यक्ष तेजस काटेकर सहित अनेक पदाधिकारी मौजूद रहे। उपस्थित नेताओं ने संजय (संदीप) भोईर को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि नया जनसंपर्क कार्यालय जनता और जनप्रतिनिधियों के बीच संवाद का प्रभावी माध्यम बनेगा तथा नागरिकों की समस्याओं के त्वरित समाधान और विकास कार्यों को गति देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। समारोह में अतिथियों का स्वागत एवं सम्मान किया गया। बड़ी संख्या में शिवसैनिकों और स्थानीय नागरिकों की मौजूदगी ने कार्यक्रम को उत्साहपूर्ण और संगठनात्मक एकता का संदेश देने वाला बना दिया।

भारी बारिश में उखड़कर गिरा विशाल जामुन का पेड़, मनापा की लापरवाही पर उठे सवाल



मीरा-भायंदर (उत्तरशक्ति)। मीरा-भायंदर महानगरपालिका के वार्ड क्रमांक 3 में लगातार हो रही भारी बारिश के बीच एक विशाल जामुन का पेड़ जड़ समेत उखड़कर सड़क पर गिर गया। गनीमत रही कि घटना के समय वहां से कोई राहगीर नहीं गुजर रहा था, अन्यथा बड़ा हादसा हो सकता था। यह घटना सोमवार सुबह 8 बजे अमर ज्योति स्कूल से ग्राउंड जाने वाले मार्ग पर मंदिर के सामने हुई। स्थानीय लोगों का आरोप है कि यदि समय रहते पेड़ की छंटाई और रखरखाव किया गया होता, तो यह स्थिति उत्पन्न नहीं होती। घटना ने मनापा की लापरवाही पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। स्थानीय निवासी स्वदेश पांडे एवं आचार्य श्यामसुंदर शर्मा ने सबसे पहले इसकी सूचना स्थानीय जनप्रतिनिधि को महानगरपालिका को दी। आरोप है कि सूचना देने के करीब दो घंटे बाद मनापा की टीम मौके पर पहुंची और प्राथमिक कटाई कर लौट गई। इसके बाद नगरसेविका दिव्या परब ने घटनास्थल का निरीक्षण किया, जिसके बाद मनापा की टीम दोबारा पहुंची और पेड़ की पूरी कटाई कर रास्ता यातायात के लिए साफ किया गया। स्थानीय नागरिकों के अनुसार, नगरसेविका योगिता शर्मा और सरिता चतुर्वेदी के मौके पर पहुंचने के बाद ही राहत कार्य में तेजी आई। नागरिकों ने मांग की है कि बरसात के मौसम को देखते हुए क्षेत्र के पुराने और जोखिम वाले पेड़ों का तत्काल सर्वे कर उनकी आवश्यक छंटाई कराई जाए, ताकि भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं से बचा जा सके।

डोंबिवली में सांसद डॉ. श्रीकांत शिंदे का दौरा, गिरी हुई दीवार का किया निरीक्षण



डोंबिवली (उत्तरशक्ति)। पिछले कई दिनों से लगातार हो रही भारी बारिश के कारण डोंबिवली शहर के कई हिस्सों में गंभीर स्थिति उत्पन्न हो गई है। इसी बीच डोंबिवली पूर्व स्थित ब्राह्मण सभा सभागार परिसर में निर्माणधीन कैसर अस्पताल के पार्किंग कार्य के दौरान लगी सुरक्षा दीवार (प्रोटेक्शन वॉल) ढह जाने से आसपास के नागरिकों में दहशत का माहौल बन गया। घटना की जानकारी मिलते ही कल्याण लोकसभा क्षेत्र के सांसद डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदे ने घटनास्थल का दौरा कर स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने संबंधित अधिकारियों से पूरी घटना की जानकारी ली और प्रभावित क्षेत्र का निरीक्षण किया। सांसद डॉ. शिंदे ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि नागरिकों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए तत्काल सभी आवश्यक सुरक्षा उपाय किए जाएं, ताकि किसी भी प्रकार की जनहानि या दुर्घटना की संभावना को रोका जा सके। उन्होंने सुरक्षा दीवार के पुनर्निर्माण का कार्य तत्काल शुरू करने, पूरे क्षेत्र को सुरक्षित करने तथा एहतियात के तौर पर स्थानांतरित किए गए परिवारों को उचित देखभाल और उन्हें हरसंभव सहायता उपलब्ध कराने के निर्देश भी प्रशासन को दिए। निरीक्षण के दौरान अभिनव गोयल, महापौर हार्थाली थाविल, उपमहापौर राहुल दामले, विधायक राणे, महापालिका के वरिष्ठ अधिकारी, अभियंता, आपदा प्रबंधन विभाग के अधिकारी-कर्मचारी, संबंधित ठेकेदार एवं स्थानीय पदाधिकारी उपस्थित रहे। इस दौरान विधायक राजेश गोवर्धन मोरे ने भी प्रशासन से अपील की कि अतिवृष्टि की स्थिति को देखते हुए पूरी सतर्कता बरती जाए और समय रहते प्रभावी उपाय किए जाएं, ताकि नागरिकों को किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े।

कल्याण रेलवे स्टेशन क्षेत्र में संगठित देह व्यापार गिरोह पर मकोका की कार्रवाई

कल्याण (उत्तरशक्ति)। कल्याण रेलवे स्टेशन परिसर में संगठित रूप से देह व्यापार संचालित करने वाले गिरोह के खिलाफ कल्याण पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (मकोका) के तहत मामला दर्ज किया है।

पुलिस के अनुसार, महात्मा फुले चौक पुलिस थाने में दर्ज अपराध बीएनएस की संबंधित धाराओं तथा अनैतिक देह व्यापार (प्रतिबंध) अधिनियम, 1956 के तहत कार्रवाई की गई थी। जांच में सामने आया कि गिरफ्तार महिला और पुरुष आरोपियों ने आपसी साठगाठ कर करीब 20 महिलाओं को पैसों का



लालच देकर देह व्यापार में धकेला और ग्राहकों से शारीरिक संबंध बनाने के लिए मजबूर कर उससे आर्थिक लाभ अर्जित किया। जांच के दौरान यह भी सामने आया कि गिरोह के सरगना और उसके सहयोगियों के पास आय का

कोई वैध स्रोत नहीं था। वे संगठित तरीके से महिलाओं और युवतियों का शोषण कर अवैध रूप से आर्थिक लाभ कमा रहे थे। इसी आधार पर मामले में मकोका की धारा के लिए पूर्व प्रादेशिक विभाग, कल्याण के अपर पुलिस आयुक्त से

विधिवत अनुमति प्राप्त की गई। पुलिस ने आरोपियों को न्यायालय की अनुमति से 30 जून को कल्याण जिला कारागार से हिरासत में लेकर मामले में औपचारिक गिरफ्तारी की। विशेष न्यायालय, ठाणे ने 6 जुलाई तक पुलिस रिमांड मंजूर की थी, जिसके बाद आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। यह कार्रवाई पुलिस आयुक्त आशुतोष डुंबरे, सह पुलिस आयुक्त ज्ञानेश्वर चव्हाण, अपर पुलिस आयुक्त संजय जाधव, पुलिस उपायुक्त अतुल झेंडे के मार्गदर्शन में की गई। मामले की आगे की जांच सहायक पुलिस आयुक्त आंशिक सहायक और उनकी टीम कर रही है।

कामन में फैक्ट्री से लाखों की कॉपर केबल चोरी का पर्दाफाश, तीन महिलाएं गिरफ्तार

मीरा-भायंदर (उत्तरशक्ति)। नायगांव पुलिस स्टेशन की अपराध जांच शाखा ने कामन स्थित एक औद्योगिक परिसर में हुई लाखों रुपये की कॉपर केबल चोरी का पर्दाफाश करते हुए तीन महिलाओं को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से चोरी की गई कॉपर केबल और वारदात में प्रयुक्त अन्य सामग्री सहित कुल 1,12,063 रुपये का माल बरामद किया है। पुलिस के अनुसार, 18 जून 2026 की रात 11 बजे से 19 जून 2026 की सुबह 8:45 बजे के बीच कामन स्थित महा एक्टिव इंजीनियर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के निर्माणधीन विद्युत संयंत्र परिसर में अज्ञात चोरों ने कंटेनर का ताला तोड़कर उसमें रकम 1,08,784 रुपये मूल्य की मल्टीस्टैंड कॉपर

केबल चोरी कर ली। इस संबंध में शिकायतकर्ता पारस संजोगकुमार डोडाल की शिकायत पर नायगांव पुलिस स्टेशन में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 305(ए) एवं 331(4) के तहत मामला दर्ज किया गया। जांच के दौरान पुलिस टीम ने घटनास्थल और आसपास के 100 से 120 सीसीटीवी फुटेज का बारीकी से विश्लेषण किया। तकनीकी जांच और गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने भिवंडी क्षेत्र से तीन महिलाओं-अंजू दिनेश गोसावी (21), सोनम विकास गोसावी (32) और पूनम संदेश गोसावी (25), निवासी अतर पाड़ा, शेला, भिवंडी-को हिरासत में लिया। फुलताछ के दौरान तीनों आरोपियों ने चोरी की वारदात में अपनी सलिपता स्वीकार कर ली।

मानखुर्द में हुआ हादसा दुर्भाग्यपूर्ण : संजीव उपाध्याय

मुंबई (उत्तरशक्ति)। पिछले चार दिनों से हो रही भारी बरसात के कारण मानखुर्द के मंडाला इलाके के जनता नगर में एक तीन मंजिला मकान गिरने से हुए दर्दनाक हादसे में छह लोगों की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए हैं। राकांपा मुंबई प्रदेश के उपाध्यक्ष संजीव उपाध्याय ने इस हादसे पर गहरा दुःख जताया है और मृतकों के परिवारों के प्रति अपनी संवेदना जताई है। उन्होंने अस्पताल प्रशासन को घायलों को अच्छा इलाज देने की भी मांग की है। बता दें पिछले कुछ दिनों से मुंबई समेत राज्य में हो रही भारी बारिश के कारण अलग-अलग जगहों पर हादसे हो रहे हैं। इसी तरह, मानखुर्द के मंडाला इलाके के जनता नगर में रविवार रात करीब 8:30 बजे एक तीन मंजिला मकान अचानक गिर गया। इस हादसे में छह लोगों की मौत हो गई है, जिसमें एक महिला और



उसके बच्चे शामिल हैं। हादसे के बाद फायर ब्रिगेड, NDRF, पुलिस और स्थानीय लोगों ने युद्ध स्तर पर बचाव अभियान चलाया। मलबा हटाने और फंसे हुए लोगों को खोजने का काम देर रात तक जारी रहा। घायलों को तुरंत शताब्दी हॉस्पिटल और राजावाड़ी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया और उनका इलाज चल रहा है। वहीं राकांपा मुंबई प्रदेश के उपाध्यक्ष संजीव उपाध्याय ने अस्पताल प्रशासन से घायलों को अच्छे से अच्छे इलाज किए जाने की मांग की है।

केलवा बांध 100% भरा, 2.951 क्यूसेक पानी का डिस्चार्ज शुरू

पालघर (उत्तरशक्ति)। लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के चलते पालघर तहसील की महिम-केलवा लघु सिंचाई परियोजना के अंतर्गत आने वाला केलवा बांध पूरी क्षमता के साथ भर गया है। जलस्तर बढ़ने के कारण बांध से 2.951 क्यूसेक पानी का नियंत्रित डिस्चार्ज शुरू कर दिया गया है। जिला प्रशासन ने संभावित जलभराव और बाढ़ जैसी स्थिति को देखते हुए निचले क्षेत्रों के नागरिकों से सतर्क रहने तथा प्रशासन के निर्देशों का पालन करने की अपील की है।

जिलाधिकारी डॉ. इंदु रानी जाखड़ ने कहा कि प्रशासन पूरी तरह सतर्क है और स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है। उन्होंने लोगों से नदी, नालों और बांध के स्थितियों (सांडवा) के पास जाने से बचने तथा किसी भी प्रकार की अफवाहों पर विश्वास न करने का आग्रह

प्रशासन अलर्ट, लोगों से नदी-नालों से दूर रहने की अपील



किया। मुंबई-सूरत पश्चिम रेलवे मार्ग पर केलवा रोड स्टेशन के समीप झांगरोली गांव के पास स्थित यह बांध वर्ष 1981 में निर्मित हुआ था और पिछले 45 वर्षों से क्षेत्र के किसानों को सिंचाई का लाभ पहुंचा रहा है। वर्तमान में बांध में 3.242 दलघमी जल भंडारण के साथ यह

100 प्रतिशत भर चुका है। संभावित बाढ़ की स्थिति को देखते हुए तहसीलदार पालघर के समन्वय में राजस्व, पुलिस और जलसंपदा विभाग की संयुक्त टीम राहत एवं सुस्था व्यवस्था में जुटी हुई है। जिलाधिकारी डॉ. इंदु रानी जाखड़ तथा पुलिस अधीक्षक यतीश

देशमुख स्वयं पूरे घटनाक्रम की निगरानी कर रहे हैं। प्रशासन ने दसमाला, भूतानमाल, झांगरोली, भरणपाड़ा, टोकराले, देवीपाड़ा, देवशेत पाड़ा, मायखोप, पाटीलपाड़ा, पलमेपाड़ा, तरडेपाड़ा, बेंदली, राटे, रावलपाड़ा और माकुणसार सहित आसपास के गांवों के लोगों से विशेष सतर्कता बरतने की अपील की है। नागरिकों से नदी-नालों में जाने से बचने, बच्चों को जलधाराओं से दूर रखने तथा किसी भी आपात स्थिति में तुरंत प्रशासन को सूचना देने का अनुरोध किया गया है। जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि फिलहाल बांध क्षेत्र के आसपास किसी प्रकार का तात्कालिक खतरा नहीं है, लेकिन लगातार बारिश को देखते हुए एहतियात बरतना अत्यंत आवश्यक है।

विक्रोली में जलभराव के बीच टायर ट्यूब डालकर अनोखा प्रदर्शन

मुंबई (उत्तरशक्ति)। मुंबई में पिछले चार दिनों से लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के कारण शहर के कई निचले इलाकों में जलभराव हो गया है, जिससे जनजीवन पूरी तरह प्रभावित हुआ है। उपनगरों के विभिन्न क्षेत्रों में सड़कों पर पानी भर गया है, जबकि पेड़ गिरने और दीवारें ढहने जैसी घटनाएं भी सामने आई हैं। विक्रोली के टैगोर नगर और कन्नमवार नगर इलाके में सड़कों में पानी भर गया है। इसी के विरोध में समाजसेवी डॉ. योगेश भालेराव ने जलभराव वाली सड़क पर टायर ट्यूब डालकर बहुरंगीय महानगरपालिका के नाला सफाई के दावों के खिलाफ अनोखा प्रदर्शन किया। पानी में ट्यूब डालकर उन्होंने प्रशासन के कार्यों पर नाराजगी जताई और नाला सफाई के दावों पर सवाल



खड़े किए। इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए डॉ. भालेराव ने कहा कि महानगरपालिका द्वारा नालों की सफाई पूरी होने का दावा जमीनी हकीकत से मेल नहीं खाता। सड़कों पर बड़े पैमाने पर जलभराव होने से आम नागरिकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि प्रशासन केवल दावे करने के बजाय प्रभावी और स्थायी उपाय

करे, ताकि हर बारिश में लोगों को ऐसी समस्याओं का सामना न करना पड़े। वहीं, विक्रोली क्षेत्र में लगातार जलभराव के कारण वाहन चालकों और पैदल चलने वालों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय नागरिकों ने इस समस्या के स्थायी समाधान की मांग करते हुए प्रशासन से तत्काल कार्रवाई करने की अपील की है।

पालघर जिले में मूसलाधार बारिश से जनजीवन पूरी तरह अस्त-व्यस्त, जिला प्रशासन ने की सतर्कता बरतने की अपील

पालघर (उत्तरशक्ति/अजीत सिंह)। पालघर जिले में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित कर दिया है। जिले के कई हिस्सों में जलभराव, सड़कों पर पानी भरने, यातायात बाधित होने तथा नदी-नालों के उफान पर आने से आम नागरिकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। निचले इलाकों में पानी भरने की स्थिति के चलते प्रशासन पूरी तरह सतर्क है। बारिश के कारण कई स्थानों पर यातायात प्रभावित हुआ है, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में संपर्क मार्गों पर पानी भर जाने से लोगों की आवाजाही में कठिनाइयां उत्पन्न हुई हैं। मौसम विभाग द्वारा आगामी दिनों में भी भारी वर्षा की संभावना जताये



जाने के बाद जिला प्रशासन ने सभी संबंधित विभागों को अलर्ट मोड पर रखा है। जिलाधिकारी डॉ. इंदु रानी जाखड़ ने नागरिकों से अपील करते हुए कहा है कि अनावश्यक रूप से घरों से बाहर न निकलें, नदी, नाले, झरनों व जलाशयों के आसपास जाने से बचें तथा किसी भी आपात स्थिति में तुरंत स्थानीय प्रशासन, पुलिस या आपदा नियंत्रण कक्ष से संपर्क करें।

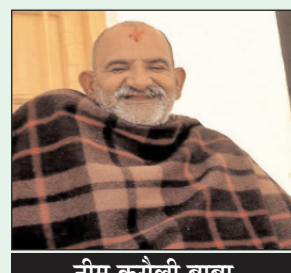
प्रशासन द्वारा संवेदनशील क्षेत्रों पर लगातार निगरानी रखी जा रही है और राहत एवं बचाव दलों को भी तैयार रखा गया है। प्रशासन ने अभिभावकों से बच्चों को बारिश के दौरान जलभराव वाले क्षेत्रों से दूर रखने तथा वाहन चालकों से सावधानीपूर्वक वाहन चलाने की अपील की है। साथ ही अफवाहों पर ध्यान न देने और केवल प्रशासन द्वारा जारी आधिकारिक सूचनाओं पर ही भरोसा करने का आग्रह किया गया है। जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि नागरिकों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है इसलिए किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएँ की गई हैं।

बालासाहेब ठाकरे जन्मशताब्दी पर शिवसेना की ओर से वरिष्ठ नागरिकों के लिए निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर व छाता वितरण

भिवंडी (उत्तरशक्ति)। शिवसेनाप्रमुख स्वर्गीय बालासाहेब ठाकरे की जन्मशताब्दी के उपलक्ष्य में शनिवार (5 जुलाई 2026) को शिवसेना शहर जिला शाखा कार्यालय के समीप स्थित शिवसेनाप्रमुख बालासाहेब ठाकरे हॉल में वरिष्ठ नागरिकों के लिए निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर एवं छाता वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) के पक्षप्रमुख एवं पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव बालासाहेब ठाकरे के निर्देश तथा शिवसेना नेता, पूर्व सांसद एवं शिवसेना सचिव विनायक राजूत के मार्गदर्शन में आयोजित किया गया। शिविर में करीब 200 वरिष्ठ नागरिकों ने भाग लिया। इस दौरान डायबिटीज जांच, टीबी जांच, सामान्य स्वास्थ्य परीक्षण, छाती का एक्स-रे सहित विभिन्न चिकित्सीय सेवाएँ निःशुल्क उपलब्ध कराई गईं। साथ ही आयुर्वेदिक दवाइयों का भी मुफ्त वितरण किया गया। कार्यक्रम

के अंतर्गत वरिष्ठ नागरिकों को वर्षा ऋतु को ध्यान में रखते हुए छाते भी वितरित किए गए। कार्यक्रम में जिला सहसंपर्क प्रमुख मनोज गणे, पूर्व शहर प्रमुख मोहन दादा वल्लट, पूर्व जिला संघटिका वैशाली मेस्त्री, जिला सचिव राजाभाऊ पुण्याथी, पूर्व महानगर प्रमुख अरुण पाटिल, पश्चिम विभाग सचिव नितेश दांडेकर तथा उपशहर प्रमुख गणेश मोरे सहित अनेक पदाधिकारी उपस्थित रहे। सभी अतिथियों ने अपने संबोधन में बालासाहेब ठाकरे के विचारों पर चलते हुए समाजसेवा को शिवसेना की पहचान बताया। इस अवसर पर उपस्थित वरिष्ठ नागरिकों ने शिवसेना द्वारा आयोजित जनहितकारी उपक्रमों की सराहना करते हुए आयोजकों का आभार व्यक्त किया और शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) के प्रति अपना समर्थन व्यक्त किया। कार्यक्रम के मुख्य आयोजक गणेश मोरे, नितेश दांडेकर, मोहन दादा वल्लट एवं अरुण पाटिल के साथ आयोजन की

सफलता में कल्पना पुजारी, अनुष्का शर्मा, इस्माईल तोडगे, मीरा भानुशाली, वर्षा पाटील, नरेश शिवादे, बाली गुळवी, मधुकर जाधव, व्यंकटेश कर्ली, एडवोकेट रोजीना मोमीन, शंकर खामकर, पुरुषोत्तम वेमूल, नौशेबा अंसारी, सरिता मजंजरेकर, नजीर शेख 'पप्पन', मुजम्मिल खान, वसीम कुंरेशी, शफीक अंसारी, सुधीर नांदुरडीकर, अजय तेजे, मयूर कदम, सुयोग घेसास, मामा पुण्याथी, शरद पांडव, महेश पाटील, विजय कुंभार, वंदना मेस्त्री एवं दीपक वाघ सहित अनेक शिवसैनिकों का विशेष सहयोग रहा।



नीम करौली बाबा

उत्तरशक्ति

* संपादक: ओमप्रकाश प्रजापति
* उप संपादक: प्रेम चंद मिश्रा
* प्रबंध संपादक: डा. शेषधर बिन्दु

उपरोक्त सभी पद अवैतनिक है।

पत्राचार कार्यालय :
उत्तरशक्ति (हिंदी दैनिक)
मुंबई-पूणे मोटर मालक श्रमजीवन प्रिमायसेस को.सो., बी-5, ए-337 ट्रक टर्मिनल डब्ल्यू.टी.टी. रोड, आर.टी.ओ. जबल, ऑटाफ हिल वडला, मुंबई-37
मो.- 9554493941
email ID- uttarshaktinews@gmail.com

प्रजापति 93245 26742
फॅब्रीकेशन अण्ड गिलवर्क्स 98200 55193
93227 55403

PRAJAPATI
FABRICATION & GRILL WORKS

MANUFACTURERS OF
COMPOUND GATES, MS GRILLS, WATER TANKS,
ROLL SHUTTER, COLLAPSIBLE DOOR &
ALUMINIUM SLIDING WINDOW

SHOP NO. 101, SAVERA CHS., LAST BUS STOP, VEERA DESAI ROAD,
ANDHERI (W), MUMBAI-400053. GST No. : 27ANKPP6297R1ZP

होटल यश पद्म में मंडलाध्यक्ष सलाहकार समिति की प्रथम बैठक संपन्न



प्रयागराज (उत्तरशक्ति)। होटल यश पद्म में जोन चेयरपर्सन डी-1 एम.जे.एफ. लायन अंजना शुक्ला के नेतृत्व में मंडलाध्यक्ष सलाहकार समिति की प्रथम बैठक सफलतापूर्वक आयोजित की गई। बैठक में लायंस क्लब इलाहाबाद अशोक, इलाहाबाद संगम एवं प्रयागराज शकुंतला के अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष तथा सर्विस चेयरपर्सन उपस्थित रहे। बैठक में बताया गया कि तीनों क्लबों ने अंतरराष्ट्रीय शुल्क का समय से पूर्व भुगतान कर अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत किया है। इस उपलब्धि पर सभी क्लबों को बधाई दी गई। मंडलाध्यक्ष की कार्ययोजना के अनुरूप प्रमुख विषयों पर चर्चा करते हुए डिस्ट्रिक्ट जॉइंट पीआरओ लायन हिमांशु गुप्ता ने ओडीओपी एवं लायंस क्वेटेड कार्यक्रम की विस्तार से जानकारी दी। वहीं, डिप्टी डिस्ट्रिक्ट गवर्नर लायन जगमोहन अग्रवाल ने सदस्यता वृद्धि और एलसीआईएफ से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी साझा की। लायन धीरेन्द्र मिश्रा ने एलएलसी विषय पर उपयोगी मार्गदर्शन प्रदान किया। बैठक में माला मिश्रा, निशा छिब्वेर, महेश अग्रवाल, मानस तिवारी, श्वेता तिवारी, पूजा केशरवानी, सुनील कुमार छिब्वेर, अविनीश केशरवानी, शिशिर कान्त सहित अनेक सदस्य उपस्थित रहे। बैठक का उद्देश्य संगठन की आगामी गतिविधियों को प्रभावी ढंग से संचालित करने के साथ सेवा कार्यों को और अधिक गति प्रदान करना रहा।

स्पीड पोस्ट की रफ्तार या सिस्टम की चूक?



ऑनलाइन ट्रैकिंग में 'डिलीवर', हकीकत में प्रेषक के पास लौटी डाक ने बढ़ाई उलझन, डिजिटल व्यवस्था में तकनीक के साथ मानवीय जवाबदेही पर भी बड़ा सवाल वाराणसी. डिजिटल भारत का सपना केवल इंटरनेट, मोबाइल एप या कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) तक सीमित नहीं है। इसका सबसे बड़ा आधार है—नागरिक का विश्वास। जब कोई व्यक्ति किसी सरकारी व्यवस्था का उपयोग करता है, तो वह केवल सेवा नहीं खरीदता, बल्कि उस व्यवस्था की विश्वसनीयता पर भरोसा भी करता है। भारतीय डाक विभाग भी इसी विश्वास की एक सदी पुरानी विरासत का नाम है। लेकिन यदि किसी स्पीड

परिणाम, बेटे की चिट्ठी, पिता का संदेश या किसी सैनिक का पत्र—सब कुछ डाकिए के हाथों से होकर गुजरता था। उस दौर में न बारकोड था, न डिजिटल ट्रैकिंग, लेकिन भरोसा इतना मजबूत था कि लोग महीनों तक धैर्य से प्रतीक्षा करते थे। समय बदला। तकनीक आई। बारकोड, ऑटोमेटिक सॉर्टिंग मशीन, ऑनलाइन ट्रैकिंग और कृत्रिम बुद्धिमत्ता ने डाक व्यवस्था को पहले से कहीं अधिक तेज और आधुनिक बना दिया। यह बदलाव स्वागतयोग्य भी है। आज कोई भी नागरिक अपने मोबाइल पर यह देख सकता है कि उसका पत्र किस डाकघर में है, कब रवाना हुआ और कब डिलीवर हुआ। लेकिन प्रश्न तब उठता है, जब स्क्रीन पर दिखाई देने वाला सच और वास्तविकता एक-दूसरे से मेल न खाए। यदि ऑनलाइन रिकॉर्ड कहे कि डिलीवरी हो गई, लेकिन कुछ दिन बाद वही पत्र वापस

भारत का पहला AI-native टिकटिंग प्लेटफॉर्म 'thumpN' हुआ लॉन्च

मुंबई। भारत का लाइव एंटरटेनमेंट बाजार दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ने वाले बाजारों में से एक है, लेकिन सही अनुभवों को खोजने के तरीके इस रफ्तार के साथ तालमेल नहीं बिठा पाए हैं। इसी अंतर को पाटने के लिए आज 'thumpN' को लॉन्च किया गया है। भारत के लाइव एंटरटेनमेंट उद्योग को दो दशकों से अधिक समय तक आकार देने वाली एक अनुभवी टीम द्वारा तैयार किया गया thumpN एक AI-native डिस्कवरी और टिकटिंग प्लेटफॉर्म है। इसे फैंस को ऐसे अनुभवों को खोजने में मदद करने के लिए डिजाइन किया गया है जो वास्तव में उनकी पसंद, व्यक्तिगत और उनके मूड से मेल खाते हैं। चाहे कन्सर्ट हों, कॉमेडी हो, नाइटलाइफ, स्पॉट्स, फेस्टिवल्स हों या उपरते हुए रिजनल इवेंट्स—thumpN लाइव मनोरंजन की पूरी दुनिया को एक ही छत के नीचे लेकर आता है। हर साल 319 शहरों में 40,000 से अधिक लाइव इवेंट्स होने के कारण, जहाँ एक तरफ फैंस विकल्पों की भरमार से भ्रमित हो जाते हैं, वहीं दूसरी तरफ आयोजकों को अपनी पहचान बनाने के लिए कड़ा संघर्ष करना पड़ता है। आज इवेंट्स को खोज सोजल मीडिया फीड, एल्गोरिदम गुगु चैट्स और लोगों से सुनी-सुनाई बातों में बिखरी हुई है। जैसे-जैसे वह बाजार महानगरों से आगे बढ़ रहा है और उपभोक्ता अधिक बातचीत वाले और पर्सनलाइज्ड अनुभवों की ओर रुख कर रहे हैं, यह कैटेगरी अब एक बिल्कुल नए डिस्कवरी मॉडल के लिए तैयार है। इस प्लेटफॉर्म के केंद्र में Shadow है, जो thumpN का एक कन्सर्नल एआई एजेंट है। इसे पारंपरिक सर्च बार के बजाय एक सहज बातचीत के माध्यम से फैंस को उनकी पसंद के लाइव अनुभव ढूँढने में मदद करने के लिए डिजाइन किया गया है।

कांग्रेसियों ने इंदौर को अवैध होर्डिंग-मुक्त बनाने की मांग, नगर निगम को सौंपा ज्ञापन



नगर निगम कमिश्नर के नाम ज्ञापन सौंपा। शहर कांग्रेस अध्यक्ष चिंटू चौकसे और नगर निगम नेता प्रतिपक्ष सोनिला मिर्मोट कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ नगर निगम मुख्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने

कहीं भी होर्डिंग लगा दिए जाते हैं। इस तरह के होर्डिंग शहर की सुंदरता को प्रभावित करते हैं। कांग्रेस नेताओं ने बताया कि एक समय नगर निगम ने इस संबंध में नीति निर्धारित की थी। इसके तहत कहीं भी अवैध होर्डिंग लगाए जाने पर निगम की टीम उन्हें रातों-रात हटा देती थी। उनका कहना है कि शहर की सुंदरता बनाए रखने के लिए इस नीति का निष्पक्ष रूप से पालन किया जाना चाहिए। इसी मांग को लेकर नगर निगम कमिश्नर के नाम ज्ञापन सौंपा गया। हालांकि, कमिश्नर के मौजूद नहीं होने पर अतिरिक्त आयुक्त ने ज्ञापन लेकर उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया।

वयोवृद्धों एवं दिव्यांगजनों को मिला सहायक उपकरण



सुल्तानपुर। जनपद सुल्तानपुर के उग्रइपुर चौराहे पर रिवार को भारत सरकार की राष्ट्रीय वयोश्री योजना के अंतर्गत वयोवृद्ध एवं दिव्यांगजन सहायक उपकरण वितरण कार्यक्रम का आयोजन

किया गया। भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम (एलिमक) द्वारा अधिकृत संस्था आदर्श आसरा के माध्यम से आयोजित इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में बुजुर्गों एवं दिव्यांगजनों को उनकी आवश्यकता के अनुरूप विभिन्न सहायक उपकरण वितरित किए गए। कार्यक्रम के दौरान लाभार्थियों को मोटरसाइकिल, व्हीलचेयर, कमीड चेयर, छड़ी, इलेक्ट्रिक छड़ी, कान की ट्रांश, बैसाखी, घुटना बेल्ट, कम्मर बेल्ट, कुशन गद्दी तथा अन्य आवश्यक सहायक उपकरण प्रदान किए गए। कार्यक्रम का आयोजन प्रभात दुबे के नेतृत्व में किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि लोकाधिकार सेवा समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं जयसिंहपुर ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि प्रभाकर चंद्रशेखर शुक्ल ने कहा कि केंद्र एवं राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ समाज के अतिम व्यक्ति तक पहुंचाना उनकी प्राथमिकता है। उन्होंने लाभार्थियों से प्राप्त उपकरणों का नियमित उपयोग करने तथा अन्य जरूरतमंद लोगों को भी सरकारी योजनाओं की जानकारी देने का आह्वान किया। कार्यक्रम का संचालन गौरव कुमार दुबे ने किया, जबकि व्यवस्थाओं की जिम्मेदारी मनीष दुबे ने संभाली। इस अवसर पर केदारनाथ, प्रेमानंद, रवि शंकर दुबे, हेमू, महेंद्र कुमार, सुमन दुबे, पवन शुक्ला सहित क्षेत्र के सैकड़ों गणमान्य नागरिक एवं ग्रामीण उपस्थित रहे। सहायक उपकरण प्राप्त करने वाले लाभार्थियों ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए आयोजकों एवं संबंधित संस्थाओं के प्रति आभार प्रकट किया। कार्यक्रम के सफल आयोजन की क्षेत्र में व्यापक सराहना की गई।

मनराज प्रतिष्ठान द्वारा निःशुल्क मेडिकल कैंप का सफल आयोजन



ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, थायरॉइड, अस्थमा एवं नेत्र जांच की निःशुल्क सुविधा उपलब्ध कराई गई। साथ ही पात्र मरीजों को निःशुल्क चश्मे भी वितरित किए गए। इस जाहतिकारी स्वास्थ्य शिविर का स्थानीय नागरिकों ने उत्साहपूर्वक स्वागत किया। 80 से अधिक लोगों ने अपनी स्वास्थ्य जांच कराई तथा विशेषज्ञ चिकित्सकों से आवश्यक स्वास्थ्य परामर्श प्राप्त किया। आयोजकों ने बताया कि स्वस्थ समाज, हमारा संकल्प अंधियान के अंतर्गत रिवार को बिल्डिंग नं. 20, एचडीआईएल, कुर्ला (पश्चिम), मुंबई-70 में एक विशाल निःशुल्क मेडिकल कैंप का सफल आयोजन किया गया। शिविर में नागरिकों के लिए

भविष्य में भी इसी प्रकार के जनसेवा एवं स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रम निरंतर आयोजित किए जाएंगे। इस अवसर पर मनराज प्रतिष्ठान के अध्यक्ष मनोज नाथानी, ईमान सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट के खलील शेख, सज्जाद शेख, फैजान शेख, आसिफ शेख, दिवाकर मंसूरी, सामाजसेवक सुखबिंदर सिंह (लाला भाई), सुखबीर सिंह, डॉ. नेहा यादव, जालिंदर साठवे, विद्यानंद यादव, हिरन पांचाळ, रेहमान शेख, किरण शेखे तथा डॉ. फरिह हाशमी सहित अनेक गणमान्य लोग उपस्थित रहे। यदि चाहें, मैं इसे समाचार पत्र प्रकाशन शैली में और अधिक प्रभावशाली शीर्षक व उपशीर्षक के साथ भी तैयार कर सकता हूँ।

मडियाहू में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन, 55 शिकायतें प्राप्त, 5 का मौके पर निस्तारण



मडियाहू, जौनपुर (उत्तरशक्ति)। उप जिलाधिकारी मडियाहू नवीन कुमार की अध्यक्षता में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया। इस दौरान विभिन्न विभागों से संबंधित

कुल 55 शिकायती प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए, जिनमें से 5 मामलों का निस्तारण मौके पर ही कर दिया गया। कार्यक्रम में उपस्थित अधिकारियों ने शेष शिकायतों को समयबद्ध तरीके से गुणवत्तापूर्ण निस्तारण के लिए संबंधित विभागों को निर्देशित किया। इस अवसर पर नायब तहसीलदार संदीप कुमार गुप्ता, खंड विकास अधिकारी रामनगर, एडीओ रामपुर अरुण कुमार यादव सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी एवं कर्मचारी मौजूद रहे।

बेहतर ग्राहक सेवा का इकाई को मिलेगा सम्मान, 15 जुलाई तक करें आवेदन



वाराणसी। उत्तर प्रदेश खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 'खादी एवं ग्रामोद्योग पुरस्कार योजना' के तहत उत्कृष्ट ग्रामोद्योग इकाइयों से आवेदन आमंत्रित किए हैं। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम एवं मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना के अंतर्गत स्थापित और पिछले तीन वर्षों से निरंतर सफलतापूर्वक संचालित इकाइयों का चयन किया जाएगा। चयनित इकाइयों को क्रमशः 15 हजार, 12 हजार और 10

हजार रुपये के पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। जिला ग्रामोद्योग अधिकारी युपी सिंह ने बताया कि इच्छुक उद्यमी निर्धारित प्रारूप में आवेदन 15 जुलाई 2026 तक जिला ग्रामोद्योग कार्यालय, टकटकपुर, वाराणसी में जमा कर सकते हैं। चयन समिति द्वारा उत्पादन, बिक्री, रोजगार सृजन तथा इकाई के समग्र प्रदर्शन के आधार पर पुरस्कार के लिए चयन किया जाएगा। अधिक जानकारी के लिए विभाग द्वारा जारी मोबाइल नंबर 9580503155 एवं 9264916036 पर संपर्क किया जा सकता है।

52 दिन बाद भी शासन को नहीं भेजी गई जांच रिपोर्ट, तहसील दिवस में डीएम को सौंपा ज्ञापन

ओबरा, सोनभद्र (उत्तरशक्ति)। तहसील दिवस के दौरान समाजसेवी राकेश केशरी ने जिलाधिकारी चर्चित गोंड को ज्ञापन सौंपकर आरोप लगाया कि उत्तर प्रदेश शासन के स्पष्ट निर्देशों के बावजूद शिकायत की जांच रिपोर्ट 52 दिन बीत जाने के बाद भी शासन को नहीं भेजी गई है। उन्होंने मामले में तत्काल कार्रवाई का मांग करते हुए शासन के आदेशों का समयबद्ध पालन सुनिश्चित कराने की अपील की। ज्ञापन के अनुसार, उत्तर प्रदेश शासन के नगर विकास अनुभाग-1 द्वारा 15 मई 2026 को जारी पत्र के माध्यम से जिलाधिकारी सोनभद्र को शिकायत की सूचना स्तर से जांच करारक स्पष्ट संस्तुति सहित तथ्यात्मक आख्या तत्काल शासन को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए थे। आरोप है कि निर्धारित समय बीत जाने के बावजूद रिपोर्ट शासन को प्रेषित नहीं की गई,



बगधा नाला से शारदा मंदिर तक करोड़ों रुपये की लागत से लगाई गई स्ट्रीट लाइटों के खराब होने, शिकायतों के बावजूद उनकी मरम्मत न होने तथा व्यापारसीढ़ीशक्ति नगर

जिससे शिकायत का निस्तारण लंबित है। ज्ञापन में ओबरा नगर क्षेत्र की कई जनसमस्याओं को भी प्रमुखता से उठाया गया। सेक्टर-9 से खैरतिया का क्षेत्र लगभग 500 मीटर क्षेत्र में नई स्ट्रीट लाइटें लगने के बावजूद उनके बंद पड़े रहने का मुद्दा उठाते हुए बताया गया कि रात में पूरा मार्ग अंधेरे में डूबा रहता है। इससे छात्राओं, महिलाओं और आम नागरिकों की आवागमन में कठिनाई होती है तथा असामाजिक तत्वों के जमावड़े की शिकायत भी की गई। इसके अलावा

मुख्य मार्ग, ओवरब्रिज और चोपन नगर पर बंद पड़ी स्ट्रीट लाइटों एवं जर्जर सड़क की समस्या भी ज्ञापन में उठाई गई। राकेश केशरी ने मांग की कि शासन के आदेश का तत्काल अनुपालन सुनिश्चित कराया जाए, लंबित जांच शीघ्र पूरी कर रिपोर्ट शासन को भेजी जाए, बंद स्ट्रीट लाइटों एवं जर्जर सड़कों की समस्या का शीघ्र समाधान कराया जाए तथा लापरवाही बरतने वाले संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही तय कर नियमानुसार कार्रवाई की जाए।

केराकत के मोहल्ला नालापार में भीषण चोरी, व्यापारियों का आक्रोश, निकाली रैली

केराकत, जौनपुर (उत्तरशक्ति)। केराकत नगर के मोहल्ला नालापार में हुई भीषण चोरी का पदाफाश अभी तक न होने पर व्यापारियों का गुस्सा उबाल पर है। सोमवार को तहसील अध्यक्ष घनश्याम जायसवाल के निर्देश पर व्यापारियों का आक्रोश सड़क पर उतरा और आक्रोशित



व्यापारियों ने पुलिस प्रशासन पर निष्क्रियता का आरोप लगाते हुए आक्रोश रैली निकाली और एस डी एम सुनील कुमार भारती व पुलिस उपाधीक्षक अजय कुमार राय को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में

19वें दिन धरने पर बैठें सौम्या बिंद की बिगड़ी तबीयत, जिला अस्पताल में भर्ती



प्रियेश गुप्ता 'रुद्र' जौनपुर (उत्तरशक्ति)। दूल्हा आजाद बिंद हत्याकांड के आरोपितों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की मांग को लेकर पिछले 19 दिनों से अनिश्चितकालीन धरने पर बैठी सौम्या बिंद की सोमवार शाम अचानक तबीयत बिगड़ गई। उनकी हालत खराब होने पर घटना स्थल पर मौजूद लोगों ने

प्रधानाचार्य श्यामलाल की सेवा को मिला सम्मान

उदयपुरवाटी। भले ही आज उनकी विदाई को सप्ताह भर होने आया, पर अब भी 36 वर्षों की उनकी शिक्षकीय साधना का सफर सबकी जुवां पर है, जो एक कर्मठता की ही बानगी है, इसका अंदाज इस बात से भी लगाया जा सकता है कि अपनी अधिवार्धिक आयु पूरी होने के बाद मिली इस भावभीनी विदाई के सम्मान से गद गद हुए बिना नहीं रह पाए खुद राजकीय महात्मा गांधी स्कूल जमात के प्रिंसिपल श्यामलाल खटौटी। आपकी बता दे 30जून को निश्चित ही भावनाओं से भरा एक उत्सव का सा माहौल था। इतनी बड़ी संख्या में मेहमान, उनके के नागरिक और इस अवसर पर शहर के नती रिश्तेदारों का आना भी उनके लगाव का ही प्रतीक था। मास्टरजी की विदाई का कार्यक्रम भावनात्मक एवं गरिमायुक्त वातावरण के बीच विद्यालय के परिसर में सेवानिवृत्ति सम्मान समारोह के रूप में आयोजित किया गया। इस अवसर पर



सर्वेदनशीलता और संतुष्टिपूर्वकता की जीवंत मिसाल रहे। उनकी सरलता, विद्यार्थियों के प्रति स्नेह और शिक्षा के प्रति समर्पण ने उन्हें समाज में एक विशिष्ट पहचान भी दिलाई। विद्यालय परिसर मानो एक ऐसे व्यक्तित्व के प्रति कृतज्ञता व्यक्त कर रहा था, जिसने अपने जीवन के 36 स्वर्णिम वर्ष शिक्षा के दीप जलाने और विद्यार्थियों के भविष्य को संवारने में समर्पित कर दिए। मिली जानकारी के अनुसार श्यामलाल ने मार्च 1990 में प्रथम विद्यार्थी ज्वॉइनिंग की। शिक्षकीय सेवा में प्रवेश करने वाले श्यामलाल खटौटी ने अपने दीर्घ सेवाकाल में विभिन्न विद्यालयों में प्रधानाचार्य एवं प्रधानाचार्य के रूप में अपनी उल्लेखनीय सेवाएँ दीं। वे केवल एक प्रशासक नहीं, बल्कि अनुशासन,

अतिथि डॉ. राजेन्द्र कुमावत चिराना (वरिष्ठ आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी उदयपुरवाटी) ने कहा कि रसेवानिवृत्ति किसी यात्रा का अंत नहीं, बल्कि अनुभवों, उपलब्धियों और समाज के प्रति नए दायित्वों की एक नई शुरुआत है। अब इनको जियोगी को अपनी तरह से जीने का, अधूरे काम पूरे करने का, समाज में सक्रिय होकर समाजोत्थान करने का मोनो अवसर मिला है। उन्होंने श्री खटौटी को शिक्षा-जगत का प्रेरणास्रोत बताते हुए एक दीर्घायु एवं निरोगी जीवन की मंगल कामनाएँ भी व्यक्त कीं। कार्यक्रम में मेहमान, शहर के गणमान्य जन, विद्यालय का रटाफ, एस.एम.सी. सदस्य, के अलावा जगदीश कुमावत सेवानिवृत्त अध्यक्ष, ललित कुमार शर्मा, सत्यनारायण अस्वाल, बसेसर शिववाल, दिलीप अस्वाल, घनश्याम सुरेंद्र, विक्रम, प्रशांत, सूबेदार,

मदनलाल, धर्मपाल, हंसराज सहित श्यामजी की धर्मपत्नी विमला देवी सहित बड़ी संख्या में मातृशक्ति और विद्यार्थी भी उपस्थित रहे। मंच संचालन श्रीमती चन्द्रकला ने प्रभावी एवं भावपूर्ण ढंग से किया। समारोह के दौरान वक्ताओं ने श्री खटौटी के व्यक्तिगत और कृतित्व पर प्रकाश डालते हुए उन्हें एक आदर्श शिक्षक, कुशल प्रशासक और समाज के सच्चे पथप्रदर्शक के रूप में याद किया। समारोह के अंत में जब श्री श्यामलाल खटौटी ने सभी के प्रति आभार व्यक्त किया, तो उपस्थित जनसमूह की आँखें नम हो उठीं। यह सेवा, समर्पण और संस्कारों से परिपूर्ण जीवन-यात्रा को समाज द्वारा दिया गया सम्मान था, जिसने यह संदेश दिया कि सच्ची निष्ठा और कर्मयोग का प्रतिफल सदैव सम्मान के रूप में ही मिलता है।

